R.N.I. : UPHIN/2012/52437
Website : www.mantrabharat.com
संस्करण : प्रयागराज
वर्ष : 15
अंक : 119
पृष्ठ : 8
मूल्य : 1.00
मंगलवार, 6 जनवरी, 2026

जुनून है सच लिखने का

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

प्रयागराज, लखनऊ, ग्वालियर एवं मुम्बई से एक साथ प्रकाशित एवं प्रतापगढ़, कौशाम्बी, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़ व गोरखपुर से प्रसारित

डाक पंजीयन संख्या : एल-2/9/रजि0/एडी0/119/15-17

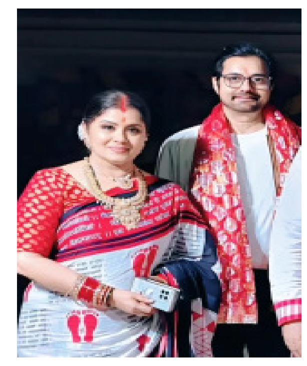

3 गंगा पूजन से शुरु हुई पंचकोशी परिक्रमा
5 डीएम व एसपी ने घोसिया धान क्रय केंद्र का ...
7 जागरण में बेकाबू हुई सुधा चंद्रन, भजन गाया ...

सिद्धरमैया सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे

बैंगलुरु **(एजेंसी)**। सिद्धरमैया छह जनवरी को कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे डी. देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उन्होंने सोमवार को इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय जनता के आशीर्वाद को दिया। उनके और उर्स के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि जहां उर्स शासक वर्ग से संबंधित थे, वहीं वह सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय (कुरुबा या चरवाहा) से आते हैं।

उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'जनता के आशीर्वाद से कल (मंगलवार को) कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का दिवंगत डी. देवराज उर्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा। गर्व की बात है कि मैं और उर्स दोनों मैसूरु से हैं।'

यह पूछने पर कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह यह रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे तो सिद्धरमैया ने स्वीकार किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनना तो दूर, मंत्री बनने की भी कल्पना नहीं की थी।

सिद्धरमैया ने कहा, 'मैंने तो बस यही सोचा था कि तालुक बोर्ड सदस्य बनने के बाद मैं विधायक बनूंगा। मैं अब तक आठ चुनाव जीत चुका हूं। मैं दो संसदीय चुनाव और दो विधानसभा चुनाव हार चुका हूं। अपने जीवन में मैंने तालुक चुनावों सहित कुल 13 चुनाव लड़े हैं।'

उन्होंने उर्स से उनकी तुलना के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'देवराज उर्स सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं थे। वास्तव में, वह शासक वर्ग से थे। वह उस समुदाय से थे जिसकी आबादी ज्यादा नहीं थी लेकिन वह एक लोकप्रिय नेता थे।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी और उर्स की कोई तुलना नहीं है। सिद्धरमैया ने कहा कि उर्स का दौर वर्तमान से भिन्न था और देवराज उर्स ने सीधे जनता से धन इकट्ठा कर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा, '1962 में लोगों ने उन्हें धन दिया और उनके पक्ष में मतदान किया। अब समय बदल गया है।'

उर्स के रिकॉर्ड को तोड़ने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सिद्धरमैया ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही होते हैं। उन्होंने खेल का उदाहरण देते हुए अपनी इस उपलब्धि की तुलना विराट कोहली द्वारा क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने से की।

असम विधानसभा चुनावों 2026 : सीएम हिमंता ने शुरू किया भाजपा का वॉल पेंटिंग अभियान, बोले- हम पूरी तरह तैयार

गुवाहाटी **(एजेंसी)**। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के दीवार चित्रकला अभियान का शुभारंभ किया। सरमा ने एएनआई से कहा कि हम इस दीवार चित्रकला अभियान को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लेंगे। असम में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है; हमारे पास लगभग 50 प्रतिशत विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार हैं... यदि हमारे पार्टी नेतृत्व ने हमें 50 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए कहा, तो हम आज शाम तक ऐसा कर सकते हैं। हम किसी भी उम्मीदवार से आवेदन नहीं लेंगे। जनता, हमारे कार्यकर्ता नाम सुझाएंगे, और हम 25, 000 रुपये या 50, 000 रुपये का कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। पहले, कांग्रेस 3 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की रकम वसूल रही है। यह प्रक्रिया 22-23 सीटों पर चल रही है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सरमा ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों से बड़ी रकम वसूल रही है। उन्होंने दावा किया कि उम्मीदवारी के लिए 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक की रकम वसूल रही है। यह प्रक्रिया 22-23 सीटों पर चल रही है। भूमि अतिक्रमण के मुद्दों का जिक्र करते हुए सरमा ने कहा कि तेजपुर में लगभग 5, 000 बीघा अतिक्रमित भूमि पर सोमवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आज हम तेजपुर में 5000 बीघा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएंगे। मिया समुदाय के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें कांग्रेस को वोट देना पड़ता है, उम्मीदवारी के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती है, और जब उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो कांग्रेस उनका साथ नहीं देती। दिलीप सैकिया एजीपी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं, और हमारे मंत्री भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह 15 फरवरी तक अंतिम रूप ले लेगा। हम बोडोलैंड और राभा में भी बातचीत कर रहे हैं।

गठबंधन के मुद्दों पर, सरमा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया असम गण परिषद (एजीपी) के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के मंत्री भी चर्चा में लगे हुए हैं और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बातचीत 15 फरवरी तक अंतिम रूप ले लेगी। भाजपा का दीवार पर चित्रकारी अभियान असम में 2026 के चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों के तहत एक प्रारंभिक जनसंपर्क पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को कामरूप जिले के चांगसारी में आयोजित एक समारोह में बेजेरा और सुआलकुची के 1, 534 छात्रों को एचएसएलसी और एचएस परीक्षाओं, 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया।

पीएम मोदी का लद्दाख पर खास ध्यान

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता संग मीटिंग में विकास-कनेक्टिविटी पर मंथन

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने सोमवार को राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में लद्दाख में जन कल्याण, प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकताओं, अवसंरचना, कनेक्टिविटी, पर्यटन और समावेशी विकास पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के आधिकारिक हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, 'लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक हैंडल ने एक्स को पोस्ट किया, 'उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। चर्चा में लद्दाख में जन कल्याण, प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकताएं, अवसंरचना, कनेक्टिविटी, पर्यटन और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।'

इससे पहले 30 दिसंबर को लद्दाख के मुख्य सचिव नामित आशीष कुंद्रा ने लेह स्थित एलजी सचिवालय में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान, उपराज्यपाल और मुख्य सचिव नामित ने प्रमुख प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शासन और विकास संबंधी मामलों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने आईएएस अधिकारी आशीष कुंद्रा को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं और लद्दाख में कुशल प्रशासन को और मजबूत करने में उनकी भूमिका पर विश्वास व्यक्त किया।

17 दिसंबर को लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और लद्दाख की विकास प्राथमिकताओं, वित्तीय आवश्यकताओं और समावेशी विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लद्दाख द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विकास कार्यों में तेजी लाने और पूरे क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।

बयान के अनुसार, राज्यपाल ने कहा, 'केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने प्रभावी प्रणालियां स्थापित की हैं, संस्थागत क्षमता को मजबूत किया है और परियोजनाओं के कार्यान्वयन तंत्र को सुव्यवस्थित किया है ताकि धन का समय पर और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।' राज्यपाल गुप्ता ने विकास की गति को बनाए रखने और उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया।

एसआईआर के दौरान 'अमानवीय' आचरण के खिलाफ अदालत का रुख करूंगी : ममता

कोलकाता **(एजेंसी)**। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान किए गए "अमानवीय" आचरण के खिलाफ अदालत का रुख करेंगी। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से जुड़े भय, उत्पीड़न और प्रशासनिक मनमानी के कारण कई लोगों की मौत हुई है और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उन्होंने कहा, "हम एसआईआर के कारण हुए अमानवीय व्यवहार और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के खिलाफ अदालत में कल याचिका दायर करेंगे।" उन्होंने कहा, "यदि अनुमति मिली तो मैं भी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर एक आम नागरिक के रूप में इस अमानवीय प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मैं एक प्रशिक्षित वकील भी हूं।" बनर्जी ने आरोप लगाया कि बिना वैध कारणों के मतदाता सूची से नामों को "मनमाने ढंग से" हटाया जा रहा है, जिससे विधानसभा चुनावों से पहले एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया डर पैदा करने वाली प्रक्रिया बन गई है। उन्होंने दावा किया कि गंभीर रोग से ग्रसित लोगों और बुजुर्ग नागरिकों को यह साबित करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर किया जा रहा कि वे वैध मतदाता हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल किया, 'अगर कोई भाजपा नेताओं के बूढ़े माता-पिता को पहचान साबित करने के लिए लाइन में खड़ा कर दे, तो उन्हें कैसा लगेगा? जब से एसआईआर शुरू हुआ है, डर से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य अस्पताल में भर्ती हैं।

इंदौर जल प्रदूषण पर बवाल : कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, मौतों का सच छिपा रही सरकार

भोपाल **(एजेंसी)**। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को इंदौर के भागीरथपुरा में पानी दूषित होने की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के कारण 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता ने क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्रिमंडल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की भी मांग की और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर इंदौर को बर्बाद करने का आरोप लगाया।

पटवारी ने कहा कि 17 नहीं, बल्कि 30 से अधिक मौतें हुई हैं। भाजपा और प्रशासन के गुंडे मीडिया को वहां की स्थिति देखने से रोक रहे हैं। अगर हर घर में सर्वेक्षण किया जाए तो मौतों की सही संख्या सामने आ जाएगी। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और महापौर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उनहोंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना कर्तव्य नहीं निभाया। मुख्यमंत्री यादव को भी अपने कर्तव्य का एहसास होना चाहिए और उन्होंने भी इंदौर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरा मानना है कि इंदौर की जनता इन मौतों का बदला जरूर लेगी।

इस बीच, इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव प्रसाद हसनी ने बताया कि 4 जनवरी तक आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या केवल छह थी। हालांकि, मौतों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है और उसकी रिपोर्ट आज शाम तक मिलने की उम्मीद है; इसके बाद ही सही आंकड़ा पता चलेगा। घटना में अब तक हुई मौतों के आधिकारिक आंकड़ों के बारे में पूछे जाने पर डॉ. हसनी ने कहा कि मौतों के आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एक समिति गठित की गई है। मृत्यु समीक्षा समिति की रिपोर्ट आज शाम तक मिलने की उम्मीद है और उसके बाद हम आपको इस संबंध में जानकारी देंगे... हमने कल दस्त से हुई मौतों की जो संख्या बताई थी, वह छह थी। समिति इस दौरान हुई अन्य सभी मौतों की जांच कर रही है। उनके दस्तावेजों की जांच और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, हम आपको आज शाम तक जानकारी देंगे। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पानी दूषित होने की घटना ने व्यापक आलोचना को जन्म दिया है, क्योंकि इसमें कई लोगों की जान चली गई और कई परिवार प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और सभी प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की थी।

केरल में लोग बदलाव चाहते हैं

के.सी. वेणुगोपाल का पिनारयी विजयन पर सीधा हमला, बोले- जनता हटाएगी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की जनता पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाली सरकार से तंग आ चुकी है और आगामी विधानसभा चुनावों में उसे सत्ता से बेदखल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ कई बैठकों के बाद वायनाड में बोलते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने पिछले दो दिनों में व्यापक विचार-विमर्श किया है और एकजुट होकर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है।

वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि एक तरफ सीपीएम सरकार को फिर से सत्ता में लाने की बात कर रही है, लेकिन जनता का मन स्पष्ट है कि वे इस सरकार को हटाना चाहते हैं। सभी लोग पूरे उत्साह और दूरदृष्टि के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम केरल में जीत हासिल करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में तेज़ी आने के बीच वेणुगोपाल की ये टिप्पणियां आई हैं। इससे पहले रविवार को, कांग्रेस नेता ने विपक्ष के नेता वीडी सतीशान के खिलाफ सीबीआई जांच की केरल सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (वीएसीबी) की सिफारिश को सिरे से खारिज करते हुए इसे चुनावों से पहले सीपीआई(एम)का राजनीतिक हथकंडा बताया था।

वेणुगोपाल ने पत्रकारों से कहा कि यह स्पष्ट रूप से चुनाव के समय की चाल है। आगामी चुनावों में कोई भी सीपीएम सरकार को नहीं बचा सकता। वे भी यह जानते हैं।' उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। वीएसीबी ने उन आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच की सिफारिश की है कि सतीशान ने पुनर्जनी आवास परियोजना के लिए अवैध विदेशी धन प्राप्त किया था। यह परियोजना 2018 में केरल में आई विनाशकारी बाढ़ में उत्तरी परवूर निर्वाचन क्षेत्र में बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई थी। इस सिफारिश में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघनों का हवाला दिया गया है और साथ ही सतीशान की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो कथित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना की गई थी।

गोवा में आप को बड़ा झटका

अमित पालेकर ने पार्टी से इस्तीफा देकर कहा- शीर्ष नेतृत्व में संवाद नहीं

पणजी **(एजेंसी)**। आम आदमी पार्टी (आप) को सोमवार को गोवा में बड़ा झटका लगा, जब वरिष्ठ नेता अमित पालेकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह घटनाक्रम जिला पंचायत चुनावों में पार्टी की करारी हार के बाद पालेकर को आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में पालेकर ने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब संवाद और परामर्श सीमित होते हैं, तो निर्णय केवल शीर्ष नेतृत्व से ही लिए जाते हैं। पालेकर ने कहा कि ऐसी बातें व्यक्तियों को कमजोर नहीं करतीं, बल्कि संस्थाओं पर दबाव डालती हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे आंदोलन के लिए, जिसने लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को पुनर्परिभाषित करने का संकल्प लिया था, यह मतभेद बेहद निराशाजनक है। पालेकर ने कहा कि उन्होंने पद या ओहदे के लिए राजनीति में कदम नहीं रखा था और आम आदमी पार्टी (आप) में इस वादे पर भरोसा करते हुए शामिल हुए थे कि यह एक 'वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति' प्रदान करेगी जो पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र और जमीनी स्तर की आवाजों के सम्मान पर आधारित होगी।

पालेकर ने कहा कि जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है, उससे इन आदर्शों में सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि, पालेकर ने आप नेतृत्व को इस अवसर के लिए धन्यवाद दिया जिससे उन्हें अपने सफर में 'सीखने' में मदद मिली। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा संगठन के हित में पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया है, उन समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना समय, विश्वास और ऊर्जा दी। मैं उन सभी का बहुत सम्मान करता हूँ। काफी सोच-विचार के बाद, मैंने यह निर्णय लिया है, क्रोध या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्पष्टता के साथ। यह निर्णय मैंने अपने सहकर्मियों और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सेंट क्रूज़ निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया है।

हालांकि, पालेकर ने कहा कि वे गोवा और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने अपने इस सफर में उनका साथ देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद भी दिया। दिसंबर में तटीय राज्य में हुए जिला पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और उसे 50 सीटों में से सिर्फ एक सीट मिली। पार्टी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया था। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 29 सीटों पर विजयी रही, जबकि उसकी सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी (एमजीपी) को तीन सीटें मिलीं।

दिल्ली दंगे साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को लगा झटका उच्चतम न्यायालय ने नहीं दी जमानत

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की 'बड़ी साजिश' से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ किया कि इन दोनों की भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में अलग और गंभीर प्रतीत होती है।

इसी मामले में जेल में बंद पांच अन्य आरोपियों के लिए राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। अदालत ने माना कि इन पांचों को अब और अधिक समय तक हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है। इन सभी को करीब 12 सख्त शर्तों के साथ रिहा किया जाएगा।

अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देते हुए यह भी कहा कि यदि गवाहों की जांच पूरी हो जाती है या अब से एक साल का समय बीत जाता है, तो वे दोबारा निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

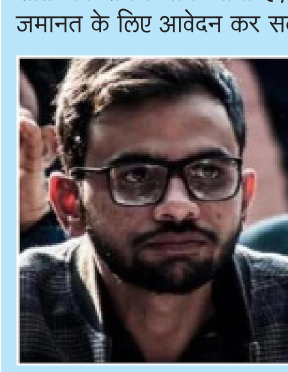

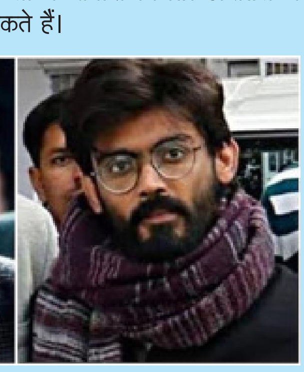

बीएसए की पहल पर माघ मेला में आये सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए खुला स्कूल

कोई भी बच्चा आउट ऑफ़ स्कूल ना रहे : सौम्या अग्रवाल

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। माघ मेला में आये हुए सफाई कर्मियों के प्रवास के लिए सेक्टर -3 में निर्मित सेनिटेशन कॉलोनी में उनके पाल्यों/बच्चों की अनवरत शिक्षा की महत्ता को अंगीकार करते हुए एक प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केन्द्र बनाया गया है। विद्याकुंभ प्राथमिक विद्यालय का शुभारम्भ श्रीमती सौम्या अग्रवाल मंडलायुक्त प्रयागराज मंडल ने आज किया। मंडलायुक्त ने विद्यालय में आईसीटी के माध्यम से शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए स्मार्ट क्लॉस, कक्षा 1 श्रृजन, कक्षा 2 विद्या अंकुर, कक्षा 3 विद्या उदय, कक्षा 4 विद्या अर्जन, कक्षा 5 विद्या पथ एवं आंगनबाड़ी केंद्र का फीता काटकर सभी कक्षा कक्षों को बच्चों को समर्पित किया गया।

इसके पूर्व मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मंडलायुक्त ने किया।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों, बच्चों एवं उनके अभिभावकों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के आयोजक बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा सेनिटेशन कॉलोनी में आवासित सफाई कर्मियों के सभी परिवारों का सर्वे के माध्यम से 03 से 14 वर्ष के बच्चों को चिन्हांकित करते हुए आयु संगत कक्षाओं में कुल 333 बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा चुका है , जिन्हें माघ मेला अवधि में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्य अतिथि श्रीमती सौम्या अग्रवाल मंडलायुक्त प्रयागराज मंडल ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा आउट ऑफ़ स्कूल ना रहे एवं उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, को ध्यान में रखते हुए विद्यालय एवं आंगनवाड़ी

केन्द्र की स्थापना की गई।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों का यह दायित्व है कि नियमित रूप से सभी बच्चों में रचनात्मक क्षमता विकसित करें एवं आधुनिक तकनीक के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करें ताकि ये बच्चे आगे चलकर सुसभ्य नागरिक बन सके एवं राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकें।

विशिष्ट अतिथि श्रीमती हर्षिका सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई खेल सामग्री , साइंस एवं मैथ किट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए ताकि बच्चे खेल।खेल से सीखना/समझना प्रारंभ करें और उनका सर्वांगीण विकास हो सके एवं संस्कारवान बन सकें।

अतिथियों ने नामांकित सभी बच्चों को निः शुल्क यूनिफॉर्म (पैंट, शर्ट, स्वेटर, जूता मोजा, कैप) तथा रमन मैगसेसे अवॉर्ड से पुरस्कृत बालिका शिक्षा को समर्पित स्वयं सेवी संस्था एजुकेट गर्ल्स द्वारा उपलब्ध कराई गई संघनित सामग्री ज्ञान का पिटारा, स्टेशनरी, अभ्यास पुस्तिका, वर्कशीट, कलाक्रॉफ्ट एवं शिव नाडर फाउंडेशन की तरफ़ से उपलब्ध कराई गई उमंग किट, टीचर लर्निंग मटेरियल बच्चों को वितरित किया गया। बच्चों द्वारा स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा बच्चों को मध्याह्न भोजन भी दिया गया।

कार्यक्रम का संयोजन राजीव त्रिपाठी जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन ने किया। उन्होंने बताया कि बच्चों को शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ इनडोर, आउटडोर प्ले मटेरियल एवं प्रतिदिन मध्याह्न भोजन कराने की व्यवस्था की गई है कार्यक्रम में विभिन्न लाभपरक योजनाओं से संबंधित विभागीय प्रदर्शनी जन सामान्य के लिए लगाई गई है, जिसका अवलोकन अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में मेला अधिकारी ऋषिराज, उप मेला अधिकारी अभिनव पाठक, डॉ आनन्द कुमार सिंह सेनिटेशन प्रभारी, दिनेश सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्रीमती संजीता सिंह सीडीपीओ, सुवैशाली शुक्ला नायब तहसीलदार, खण्ड शिक्षा अधिकारी लालशर्मा, विमलेश त्रिपाठी, अखिलेश यादव, एजुकेट गर्ल्स संस्था की ओर से अभिनव दुबे, आशीष रॉय, मनीष कुमार यादव, सुनेहा सिंह, प्रभाशंकर, शशिप्रकाश, कुंवर, श्रीमती शालिनी, सुउर्वशी, पंकज, शिवनाडर फाउंडेशन की ओर से डॉ शरद मिश्रा, कार्तिकेय पांडे, विद्याकुंभ विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार मिश्रा व सम्पूर्ण विद्यालय स्टॉफ विनोद पांडे, शशिकांत मिश्रा, शशांक मिश्रा, कुलदीप कुमार द्विवेदी आदि उपस्थित रहे।

भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ तहसील सोराम की बैठक संपन्न

मंत्र भारत संवाददाता

सोरांव। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. भगवान प्रसाद उपाध्याय के निर्देशन में तहसील सोराम में क्षेत्रीय पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गंगापार जिलाध्यक्ष श्याम कृष्णा उर्फ पिंटू शुक्ला की विशेष उपस्थिति रही।

बैठक की अध्यक्षता तहसील संरक्षक राजन तिवारी ने की। इस दौरान संगठन के विस्तार और मजबूती पर चर्चा के साथ-साथ पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। वक्ताओं ने पत्रकार हितों की रक्षा, एकजुटता और संगठन को और सशक्त बनाने पर जोर दिया।

बैठक में तहसील अध्यक्ष रामू भैया पाण्डेय रवि पटवा धनंजय पांडे, मो गुलफाम सिद्दीकी, ईथिलेश तिवारी, कृष्ण मोहन मौर्य, अनिल कुमार पांडे, संजय कुमार सहित क्षेत्र के तमाम पत्रकार उपस्थित रहे।

इलाज के नाम पर मौत का कारोबार, जिम्मेदार मौन

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। जिले में निजी क्लीनिकों, अस्पतालों और नर्सिंग होम में हो रहे कथित जोखिम भरे इलाज को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि जिले के कई निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर गरीब और मजबूर मरीजों के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान लेने से बच रहे हैं।

बताया जा रहा है कि इन क्लीनिकों और अस्पतालों के बाहर बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर नामचीन डॉक्टरों के आने-जाने का दावा किया जाता है, जबकि अंदर की हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। आरोप है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की लापरवाही के चलते गरीब मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर भर्ती कर लिया जाता है। मरीजों से कहा जाता है कि यहां बड़े डॉक्टर इलाज करते हैं, जिस पर भरोसा कर परिजन मरीज को भर्ती करा देते हैं।

सूत्रों के अनुसार जब तक मरीज के परिजनों के पास पैसा रहता है, तब तक इलाज चलता रहता है। जैसे ही आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, उसे प्रयागराज रेफर कर दिया जाता है। आरोप यह भी है कि रेफर किए गए अस्पतालों से भी कमीशन लिया जाता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई अस्पतालों में बिना किसी मान्य डिग्री के लोग इलाज कर रहे हैं। यहां तक कि आठवीं-दसवीं पास युवकों से बड़े-बड़े ऑपरेशन कराने का दावा किया जाता है। इसके बावजूद ऐसे अस्पतालों और कथित डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे सीएमओ कार्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

आरोप है कि कुछ निजी अस्पताल सरकारी डॉक्टरों को बुलाने के नाम पर भी मरीजों से अतिरिक्त पैसे वसूलते हैं। वहीं कुछ संचालक खुद को पत्रकार बताते हुए यह कहकर दबाव बनाते हैं कि यदि उनके खिलाफ कोई खबर प्रकाशित हुई तो वे उसका खंडन कर देंगे।

मूरतगंज, बलिहावां देह, इमामगंज, काजीपुर, सैयद सरावां और चायल सहित जिले के कई इलाकों में क्लीनिकों और अस्पतालों की भरमार है। जांच करने पर सामने आता है कि कई जगह इलाज करने वालों के पास न तो मेडिकल डिग्री है और न ही हाईस्कूल-इंटरमीडिएट के बाद की कोई वैध योग्यता, फिर भी वे खुद को बड़े डॉक्टर बताकर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं।

अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और कब तक इलाज के नाम पर यह कथित मौत का कारोबार यूं ही चलता रहेगा।

लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में इस बार दिखेगी कैंपस मस्ती और मथुरा के व्यंजनों का स्वाद

मंत्र भारत संवाददाता

वाराणसी। कलर्स का 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' इस वीकेंड हंगामे और यादों के सफर को और बढ़ाने वाला है। शो की रसोई इस बार कॉलेज की मस्ती से लेकर मथुरा के समृद्ध स्वादों तक का सफर तय करेगी। सेट को कैंटीन वाइब्स और कॉरिडोर वाली मस्ती के साथ एक युवा रूप दिया गया है, जहाँ ह्यूमर ही मुख्य 'सिलेबस' होगा। कश्मीरा शाह एक ड्रामेटिक कॉलेज ट्रस्टी की भूमिका में कमान संभालेंगी, वहीं ऐशा सिंह, ईशा मालवीय और जन्नत जुबैर ऊर्जावान छात्राओं के रूप में ग्लैमर और कैंपस का धमाल लेकर आएंगी। इस ग्लैमर के विपरीत अभिषेक कुमार और समर्थ जुरैल पूरी तरह से 'बैकबेंचर' अवतार में नजर आएंगे; पाजामा, शॉर्ट्स और गले में स्नैक्स लटकाए हुए वे मजेदार 'कैंटीन वाले दादा' की भूमिका में दिखेंगे। एपिसोड के सबसे शानदार पलों में से एक तब आता है जब कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा और शेफ हरपाल सिंह सोखी की प्रतिष्ठित 'सैयारा' एंट्री को रीक्रिएट करते हैं। इस बार वे इसमें एक ट्विस्ट जोड़ते हुए शेफ हरपाल की पत्नी को भी साथ लाते हैं, जिससे पूरा सेट ठहाकों से गूंज उठता है। 'कहानी जन्नत की' सेगमेंट के दौरान माहौल भावुक हो जाता है, जहाँ जन्नत जुबैर एक 'टेड टॉक' के अंदाज में अपनी प्रेरक यात्रा साझा करती हैं–महज 6 साल की उम्र में ऑडिशन देने से लेकर 10 साल की उम्र में कलर्स के शो 'फुलवा' से अपने कॅरियर की शुरुआत और आज एक स्टार बनने तक का सफर।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिन्दू वाहिनी संघ एवं बजरंग वाहिनी संघ ने निकाली आक्रोश रैली

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नर संहार अत्याचार व हत्याओं का शीर्षिला थामने का नाम नहीं ले रहा आए दिन हिन्दू समाज के लोगों को मारा पिटा व जिन्दा जलाया जा रहा है ऐसे समाचार विभिन्न मीडिया संसाधनों से मिल रहे है पर बंगलादेश की युनुस सरकार बराबर इसमें शरीक दिखाई पड़ती है वह कट्टर पंथियों पर कोई कार्यवाही करती नहीं दिखती अंतरराष्ट्रीय जगत भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है जिससे वहां के हिन्दुओं को समाप्त करने की युनुस सरकार की मंशा मजबूत हो रही है। अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन भी शांत दिख रहा है।

ज्ञात हो कि हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ जन आक्रोश चरम पर पहुंच चुका है आज हिन्दू वाहिनी संघ एवं बजरंग वाहिनी संघ के कार्यकर्ताओं ने शिव शक्ति धाम सराय अकिल से फकीराबाद चौराहे तक हिंदू वाहिनी संघ एवं बजरंग वाहिनी के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई ।

गगनभेदी नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री युनुस खान मुर्दाबाद का नारा लगाया व उनका पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। प्रदेश महामंत्री भास्करानंद उर्फ श्याम जी ने कहा कि हिंदू समाज पर कहीं भी अत्याचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में हो रही घटनाएं मानवाधिकारों पर सीधा प्रहार हैं। केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। रैली में प्रदेश सचिव गौ रक्षा प्रकोष्ठ के हिंदू रामबाबू, जिला प्रभारी संदीप मिश्रा, जिलाध्यक्ष छविनारायण तिवारी, नितिन केसरवानी, बबलू जिला अध्यक्ष गौ रक्षा प्रकोष्ठ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान जोश और अनुशासन देखने को मिला। प्रशासन की सतर्कता के बीच प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रैली ने साफ संदेश दिया की हिंदू समाज के मुद्दों पर कौशाम्बी की धरती से उठी आवाज अब चुप नहीं बैठेगी। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से हस्तक्षेप की मांग की।

कल्पवास जीवन को साधना में रूपांतरित करने की सात्विक परंपरा : डॉ. अलका प्रकाश

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जब गंगा-यमुना के तट पर आस्था, साधना और संस्कृति का संगम सजीव होता है, तब शब्द केवल अभिव्यक्ति नहीं रहते, वे जीवन-दर्शन बन जाते हैं। इसी भावभूमि पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'चलो मन गंगा-यमुना तीर' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 'शब्द-ब्रह्म' संगोष्ठी में कल्पवास की सात्विक परंपरा और भारतीय जीवन दर्शन पर गहन विमर्श हुआ।

सांस्कृतिक केंद्र के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित संगोष्ठी के दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा एवं वक्ताओं ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इस अवसर पर केंद्र निदेशक ने सभी वक्ताओं को अंगवस्त्र एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया।

'कल्पवास : सात्विक परंपरा एवं जीवन दर्शन' विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. अलका प्रकाश ने कहा कि कल्पवास भारतीय अध्यात्म की वह सात्विक साधना है, जहाँ मनुष्य प्रकृति, संयम और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध करता है। यह परंपरा त्याग, तप, सत्य और करुणा को दैनिक आचरण में उतारने का अभ्यास कराती है। सादा आहार, सीमित आवश्यकताएँ और ब्रह्ममुहूर्त की साधना मन को

विकारों से मुक्त करती है। उन्होंने कहा कि कल्पवास में जीवन को उपभोग नहीं, बल्कि साधना मानने का दर्शन निहित है, जो मनुष्य को आत्मबोध, सामाजिक समरसता और नैतिक जीवन की ओर उन्मुख करता है।

वरिष्ठ लेखक एवं आलोचक डॉ. रविनंदन सिंह ने कहा कि कल्पवास की सात्विक परंपरा ज्ञान, भक्ति और आस्था का समन्वय है। यह सत, रज और तम–तीनों गुणों को संतुलित करने की परंपरा है, जिसमें जीवन में रहते हुए मोक्ष की अनुभूति और वीतरागी बनने का भाव निहित है। उन्होंने इसे चिंतन, मनन और साधना की परंपरा बताते हुए कहा कि यह शरीर और मन के सम्यक योग, भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग का संतुलित स्वरूप है। इंद्रिय-निग्रह, आत्मबोध और आंतरिक यात्रा इस परंपरा के मूल तत्व हैं, जिनके पीछे भारतीय जीवन दर्शन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण निहित है।

इसके बाद गुरुबाणी के अंतर्गत नव ज्योति सिंह (गुरुद्वारा सभा) द्वारा गुरु नानक देव की वाणी 'एक ओंकार सतनाम करता पुरखष्ठ' का भावपूर्ण गायन प्रस्तुत किया गया। इस शबद के माध्यम से उन्होंने मानवता, सत्य, समरसता और ईश्वर की एकात्मकता का संदेश दिया। गुरुवाणी की मधुर प्रस्तुति से सभागार आध्यात्मिक भाव से सराबोर हो उठा कार्यक्रम का संचालन संजय पुरषार्थी ने किया तथा कार्यक्रम सलाहकार कल्पना सहाय ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन

कौशाम्बी। जनपद के मंझनपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत गुवारा तैयबपुर गांव में नए साल के अवसर पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

ज्ञात हो कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कड़ाके की ठंड में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के तहत कौशाम्बी जनपद के पत्रकार शिवा यादव द्वारा आसपास के गांवों के लगभग 50 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। यह कंबल वितरण सनईपर, दरियापुर, भैला मकदूमपुर, गुवारा तैयबपुर सहित अन्य गांवों के बुजुर्गों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को किया गया। कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और उन्होंने इस मानवीय पहल के लिए पत्रकार शिवा यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पत्रकार शिवा यादव ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से अपील की कि वे आगे आकर गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड, भूख या अभाव से पीड़ित न रहे। उन्होंने भविष्य में भी समाजसेवा के ऐसे कार्य निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित सहयोगियों ने भी सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह के आयोजन न केवल जरूरतमंदों को तत्काल राहत देते हैं, बल्कि समाज में आपसी सहयोग और मानवता की भावना को भी मजबूत करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आयुष, विजय विश्वकर्मा, बड़कू यादव, दुर्गेश, राम अभिलाष, करन, अयोध्या, प्रदीप और अजीत सहित कई लोगों का सक्रिय सहयोग रहा।

महिला सुरक्षा व सरकारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में पुलिस ने किया महिलाओं को जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन पुलिस द्वारा महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान' के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक व मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह थाना शोहरतगढ के निर्देशन में थाना क्षेत्र ग्राम जमहिरिया की बच्चियों/महिलाओं को जागरूक किया गया तथा खुद के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे मे जानकारी दी गयी दहेज उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट महिला संबन्धित मुकदमों में पीड़िताओं की काउंसलिंग की गई तथा मिशन शक्ति 5.0 स्टीकर भी चस्पा किया गया । मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति फेज 5.0 के विषय मे महिलाओं को महिला सम्वन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में उप निरीक्षक राजकुमार यादव, मुख्य आ?क्षी अविनाश सिंह आरक्षी पवन मौर्या, महिला आरक्षी उर्मिला देवी, शोभा भारती, अंबिका ने किया जागरूक।

कार्यालय नगर पालिका परिषद गोपीगंज, जनपद- भदोही।

पत्रांक : 595 / न0पा0प0गो0 / 2025 दिनांक : 5-1-2026

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद गोपीगंज जनपद-भदोही के वार्षिक ठेकों की सार्वजनिक नीलामी (ग्राम गोपीगंज टाउन बाहर वार्ड नं0 03 में स्थित तालाब गाटा संख्या-337 के मत्स्य पालन हेतु) वर्ष 2025-26 दिनांक 07.01.2026 को समय प्रातः 11.00 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद गोपीगंज जनपद भदोही के सभागार में होगी । इच्छुक व्यक्ति समय से उपस्थित होकर बोली में प्रतिभाग कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी शर्तनामा की जानकारी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

प्रस्तावित नीलामी का विवरण

क0 सं0	प्रस्तावित सम्पति का विवरण	गाटा सं0 / रकवा	अवधि	अन्य विवरण
1	जलमग्न तालाब टाउन बाहर वार्ड नं0 3 गोपीगंज	337/1.9400	05 वर्ष	

राम बचन यादव
(अधिशासी अधिकारी)
नगर पालिका परिषद गोपीगंज
जनपद - भदोही

जितेन्द्र गुप्ता
(अध्यक्ष)
नगर पालिका परिषद गोपीगंज
जनपद-भदोही

कार्यालय उप निदेशक मत्स्य, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज

पत्रांक : 759 / गुलरिया जला0 निविदा म0-प्रयागराज/2025-26 दिनांक- 01.01.2026

श्रेणी -तीन की जलाशय निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से मत्स्य विभाग उ0प्र0 के प्रबन्धान्तर्गत प्रयागराज मण्डल के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में स्थित श्रेणी-तीन के जलाशय में मत्स्य पालन/मत्स्याखेट हेतु ''जहॉ है जैसे है'' की स्थिति में निविदा दस वर्शों हेतु मत्स्य उत्पादन अनुभाग उ0प्र0 शासन से निर्गत शासनादेश संख्या-28/2023/756/ सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25 सितम्बर 2023, तत्संबंधी शुद्धिपत्र संख्या 31/1499/ सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 19 अक्टूबर 2023, शासनादेश संख्या-1514/सत्रह-म-2024-17-1005/3/2024 दिनांक 04 अक्टूबर 2024 एवं शासनादेश संख्या-4/2025/132/सत्रह-म-2025-17-1099/63/2022 दिनांक 29 जनवरी 2025 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप एवं शासनादेश द्वारा गठित निविदा समिति के समक्ष निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदायें आमंत्रित की जाती हैः-

क्र0 सं0	जलाशय का नाम व श्रेणी/ जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	मत्स्य पालन/ मत्स्याखेट अवधि	प्रथम वर्ष 2025-26 हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य (लाख में)	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खुलने की तिथि एवं समय	बयाने की धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा खुलने का स्थल	निविदा प्रपत्र का शुल्क (रू0में)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	गुलरिया श्रेणी-03	308.00 हे0	प्रथम वर्ष की अवधि स्वीकृत तिथि से 30.06. 2036 तक (दस मत्स्य वर्श)	रू0 8.60 लाख (रूपया आठ लाख साठ हजार)	निविदा दिनांक 20.01.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे तक	निविदा दिनांक 20.01.2026 दोपहर 1.00 बजे	रू0 0.86 लाख (रूपया छियासी हजार)	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन, प्रयागराज	रू0 100.00 (रूपया सौ)

मत्स्य वर्ष से तात्पर्य ग्रिगेरियन कैलेण्डर वर्ष की 01 जुलाई से अगले वर्ष के ग्रिगेरियन कैलेण्डर की 30 जून से है।

1. यदि दिनांक 20.01.2026 को निविदा नहीं हो पाती है या उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है, तो दिनांक 27.01.2026 को पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही होगी तथा यदि दिनांक 27.01.2026 को भी जलाशयों की निविदा नहीं हो पाती है या उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है तो दिनांक 02.02.2026 को पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही उपरोक्त निर्धारित समय एवं नियत स्थान पर होगी।
2. निविदादाता प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु निर्धारित धनराशि (निविदा प्रपत्र मूल्य तथा बयाने की धनराशि) का पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट (उप निदेशक मत्स्य प्रयागराज के पदनाम से बनवाकर) निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 19.01.2026 को सांय 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा इसके उपरांत ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा सकता है।
3. निविदा समिति को किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा नवीन शासनादेश के अनुसार निविदा की विस्तृत शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उप निदेशक मत्स्य, 43 काटजू रोड प्रयागराज से प्राप्त की जा सकती है।

(विजयपाल)
उप निदेषक मत्स्य विभाग
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

U.P. : 243547 दिनांक : 05.01.2026 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

भारतीय संस्कृति एवं परम्परा सम्पूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय- न्यायमूर्ति (पू.) सुधीर नारायण

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। परिसरीय सभागार में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गङ्गानाथ झा परिसर, प्रयागराज एवं प्रयाग विद्वत्परिषद् के संयुक्त तत्त्वावधान में पञ्चदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारम्भ परिसर के निदेशक प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यशाला का शुभारम्भ मंगलाचरण एवं कार्यक्रम के मुख्यातिथि प्रो. आचार्य सत्यकाम, कुलपति, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, सारस्वतातिथि डा. वेंकट रामानाथन, समन्वयक, भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र, आई.आई.टी., बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एवं भारतीय ज्ञान परम्परा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति सुधीर नारायण के करकमलों द्वारा दीपप्रज्ज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के सारस्वतातिथि डा. वेंकट रामनाथन ने अपने वक्तव्य में भारतीय ज्ञान परम्परा में नवीन शोध कार्यों की अपार सम्भावनाओं को खोजने हेतु आयोजित की जाने वाली इस कार्यशाला को अतिमहत्त्वपूर्ण बताया। मुख्यातिथि प्रो. आचार्य सत्यकाम ने भारतीय ज्ञान परम्परा की समृद्धता से उपस्थित जनों का परिचय कराया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा को ऐसी गंगा के रूप में परिभाषित किया जिसमें विभिन्न ज्ञान रूपी नदियाँ समाहित हो रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परिसर के निदेशक प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी ने इस कार्यशाला को औपचारिक शोध के साथ साथ शोध की असीमित संभावनाओं को अन्वेषित करने का माध्यम बताया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा में अनुसंधान आरम्भ करने से पूर्व अनुसंधान के

औचित्य को विशेष रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परम्परा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान हेतु माननीय न्यायमूर्ति सुधीर नारायण, भूतपूर्व न्यायमूर्ति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विशेष अभिनन्दन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति (पूर्व) सुधीर नारायण ने भारतीय ज्ञान परम्परा के क्षेत्र विष्णुसहस्रनाम के प्रत्येक श्लोक की चित्रमय प्रस्तुति का उल्लेख करते हुए उपस्थित विद्वज्जनों के समक्ष अपनी पुस्तक हेतु किये गये प्रयोगों से परिचित कराया। उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं को सम्पूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय बताया।

समस्त अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत उक्त कार्यक्रम के संयोजक प्रो. देवदत्त सरोदे ने करते हुए भारतीय ज्ञान परम्परा के विषय में सभी को योगदान देने हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेताया कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान के प्रति उदासीनता रहने वाले व्यक्ति को भविष्य में स्वयं को ही जवाब देना होगा। कार्यक्रम के अन्य संयोजक वरिष्ठ पत्रकार एवं समन्वयक, प्रयागराज विद्वत परिषद् पण्डित वीरेन्द्र पाठक ने महर्षि भरद्वाज के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यशाला को महर्षि भरद्वाज के विषय में विस्तार से जानने, समझने एवं अनुसरण करने का अद्वितीय अवसर बताया। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु परिसर के निदेशक प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी को विशेषतः धन्यवाद दिया तथा माननीय न्यायमूर्ति (पू.) सुधीर नारायण के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यशाला के सहसंयोजक डॉ. यशवन्त कुमार त्रिवेदी ने किया। इस अवसर पर प्रो. रामकृष्ण पाण्डेय 'परमहंस', प्रो. मनोज कुमार मिश्र, डॉ. सुरेश पाण्डेय, संजय कुमार मिश्र, राजेशकान्त तिवारी, अंकित मिश्र, सुअश्विनी लंके, रामसुरेश तिवारी परिसरीय अन्य कर्मचारी एवं अधिकारीगण तथा देश के विभिन्न प्रान्तों से कार्यशाला में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं के साथ अन्य शोध छात्र-छात्राएँ समुपस्थित रहे। सधन्यवाद प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रोटरी इलाहाबाद द्वारा निःशुल्क दवा व फल किया गया वितरित

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। रोटरी इलाहाबाद के अध्यक्ष राजीव रंजन अग्रवाल के नेतृत्व में मेडीमैक्स हॉस्पिटल के सहयोग से वृद्धाश्रम में सेवा एवं करुणा से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृद्धजनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क दवाइयां एवं पौष्टिक फलों का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य में राजेश अग्रवाल का विशेष योगदान रहा तथा डॉ. अशोक कुमार शुक्ला ने भी सहयोग प्रदान किया।

कार्यक्रम में मेडीमैक्स हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. शरद गुप्ता एवं डॉ. यादव ने अपनी सेवाएँ प्रदान कीं और वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया।

रोटरी इलाहाबाद का यह मानवीय प्रयास समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, संवेदना एवं सेवा भावना का सशक्त रूप से दर्शाता है।

ओम नमः शिवाय की ओर से दर्जनभर स्थानों पर चल रहा विशाल भण्डारा

पंच तेरह भाई त्यागी, मां सीता की रसोई की ओर से चल रहा विशाल भण्डारा

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। माघ मेला के पहले मुख्य स्नान पर्व पौष पूर्णिमा से मेला क्षेत्र में चल रहे दर्जनभर भण्डारे में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन, रात लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे है। यह भण्डारा श्रद्धालुओं के लिए दिन, रात चलना शुरू हो गये है जो जहां लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे है। माघ मेला मे सबसे बडा भण्डारा ओम नमः शिवाय का दर्जन भर स्थानों पर दिन, रात चल रहा है। शिविर के व्यवस्थापक शिवम ने बताया कि भण्डारे मे बहुत अधिक भीड हो रही है संभावना है कि 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया है। पंच तेरह भाई त्यागी नया घाट अयोध्या के महामण्डलेश्वर स्वामी गोपाल महराज ने बताया कि शिविर मे विशाल भण्डारा अनवरत चल रहा है। जहां भीड प्रसाद ग्रहण कर रही है।

मां सीता की रसोई की डायरेक्ट श्रीमती मनप्रीत कौर ने बताया कि संस्था की ओर से मेला क्षेत्र में दर्जनभर स्थानों भण्डारा चलाया जा रहा है जहां बडी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे है। यह भण्डारा माघी पूर्णिमा तक दिन, रात चलता रहेगा। हरियाणा के चरखी दादरी आश्रम, नागेश्वर धाम, हरियाणा के राघौर आश्रम, बालानंदाचार्य नगर, कोल्हू नाथ खालसा, मां सीता की रसोई की ओर से विशाल भण्डारा आज से शुरू हो गया है जहां लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे है।

शिक्षा सागर फाउंडेशन ने चार शिक्षिकाओं को किया सम्मानित

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। शिक्षा सागर फाउंडेशन राजस्थान ने जिले की चार शिक्षिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया है.इनमें शिक्षिका श्रीमती सुनीता कनौजिया पीएस बसहरा जसरा, पधमिनी नेवादा समोगरा चाका, अनुपमा श्रीवास्तव कार्यवाहक प्रधानाचार्या उप्र वि बरबोझा करछना और श्रीमती नीलकमल सहाय संविलियन विधालय जलालपुर घोसी भगवतपुर है। इन शिक्षिकाओं को शिक्षा सागर फाउंडेशन राजस्थान राष्ट्रीय कान्तिकारी नवाचारी शिक्षक सम्मान -2026 से सम्मानित किया गया है। सम्मानित शिक्षिका श्रीमती सुनीता कनौजिया ने सम्मानित किए जाने पर संस्था के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

सद्विद्या ही समाधान कार्यक्रम की भावपूर्ण विदाई

गुरूकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार निर्माण की प्रयोगशाला : स्वामी चिदानन्द सरस्वती

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज/अहमदाबाद। स्वामी नारायण गुरूकुल अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित 'सद्विद्या ही समाधान' कार्यक्रम की विदाई समारोह में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती के पावन सान्निध्य ने उपस्थिति श्रद्धालुओं व युवाओं की चेतना में अमिट छाप छोड़कर इस समारोह को ऐतिहासिक बना दिया। लगभग 15 हजार श्रद्धालुओं से खचाखच भरे विशाल मैदान में यह कार्यक्रम शिक्षा, संस्कृति, सेवा, साधना, संस्कार और राष्ट्रभाव का विराट उत्सव बनकर उभरा।

स्वामी नारायण गुरूकुल के पूज्य संतों ने अपने जीवन से जो मिसाल कायम की, वही आज समाज के लिए मसाल बन गई। सेवा-परायण महंतों और पूज्य संतों की वाणी, आचरण और दृष्टि ने स्पष्ट कर दिया कि गुरूकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार निर्माण की प्रयोगशाला है। यहाँ शिक्षा प्रदर्शन नहीं, दर्शन है। यहाँ कला केवल मंच पर नहीं, बल्कि जीवन में उतरती है। स्वामी ने स्वामी नारायण गुरूकुल के पूज्य संत पूज्य माधवप्रियदासस्वामी, पूज्य पुरानी बालकृष्णदासस्वामी, भक्त वत्सल स्वामी जी, राम स्वामी जी, हरेकृष्णा स्वामी जी, आचार्य रामप्रिय जी, अनेक पूज्य संत और गुरूकुल के सभी आचार्यो को धन्यवाद देते हुये कहा कि आपके अथक प्रयासों से गुरूकुल की दिव्य परम्परा स्वामी नारायण गुरूकुलों के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से संचालित हो रही हैं। इस अवसर पर जीतू भाई, सोनाग्रा, अडानी ग्रुप से रमेश शाह एवं अनके उद्योगपति व सम्मानित वृंद उपस्थित थे।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में सक्रिय हुई सीसी टीम, अवैध पार्किंग हटाकर यातायात व्यवस्था सुदृढ़

मंत्र भारत संवाददाता

सोरांव। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत नेशनल हाईवे हंडिया कोखराज मार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सीसी टीम क्रिटिकल कॉरिडोर द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है हंडिया-कोखराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर टीम ने हाईवे किनारे और मार्ग पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया तथा अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्ती दिखाई।सीसी टीम क्रिटिकल कॉरिडोर की संयुक्त टीम ने अभियान के दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया। साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।इस अभियान का नेतृत्व टीम प्रभारी उप निरीक्षक अजीत वर्मा कर रहे हैं। उनके साथ एन एच आई टीम के अभिषेक यादव समेत अन्य पुलिसकर्मी हाईवे पर यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

नगर निगम राम सेतु का निर्माण कर प्रयागराज की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ेगा : महापौर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का बनाएंगे हम प्रयागराज

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जन्मदिवस आयोजन समिति के द्वारा पजावा रामलीला कमेटी अतरसुइया में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जन्म जयंती और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और महापौर गणेश केसरवानी का जन्मदिन समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर सुंदरकांड पाठ का और प्रसाद वितरण आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ मुरली मनोहर जोशी को जन्मदिन की बधाई दी गई और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके विकास कार्यों पर दर्शन डाला गया इस अवसर महापौर गणेश केसरवानी ने कार्यक्रम में आएं। सभी अतिथि गणों का आभार व्यक्त और कहा कि पूज्य कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का जीवन राष्ट्र एवं राम काज के प्रति समर्पित रहा है और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़े हैं और उन्हीं के आदर्श पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का प्रयागराज हमें बनाना हैं और उन्होंने नगर निगम के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए की नगर निगम सरकार ने इन दो वर्षो में विकास की धारा बहाई है और बहुत जल्द नगर निगम सरकार राम सेतु का निर्माण करने जा रहा जो हमारे प्रयागराज की सांस्कृतिक विरासत को जोडेगा। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह गौर, जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह,

क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, यमुना पार जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विदुप अग्रहरि, मुरारी लाल अग्रवाल, राम केसरवानी नीरज त्रिपाठी, राजेश केसरवानी ने महापौर के विकास कार्यों पर दर्शन डाला। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व पार्षद प्रभाकर मिश्रा गिरी बाबा रहे। संचालन प्रमोद मोदी, राजेश केसरवानी एवं सुभाष वैश्य ने किया। इस अवसर अनिल गुप्ता, विजय वैश्य, प्रमिल केसरवानी, शशि वार्ष्णेय, राजेश शुक्ला, रणजीत सिंह, कुंज बिहारी मिश्रा, पदुम जायसवाल, विष्णु त्रिपाठी, रवि शुक्ला, गोपाल मालवीय, एवं पार्षद गण, व्यापारी नेता, एवं भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने महापौर गणेश केसरवानी को जन्मदिन की बधाई दी ।

'मिशन शक्ति 5.0' अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज महोदय व अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज महोदय के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त यमुनानगर के कुशल पर्यवेक्षण में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत जोन यमुनानगर के समस्त थानों की मिशन शक्ति /एंटी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बालिकाओं व महिलाओं को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे- सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, सामूहिक विवाह योजना, चिकित्सा संबंधी आयुष्मान योजना व हेल्पलाइन नंबर जैसे- वूमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर की दी जानकारी।

गंगा पूजन से शुरु हुई पंचकोशी परिक्रमा शामिल हुए अखाडों के संत, महात्मा, अफसर

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे माघ मेले में सोमवार को पांच दिवसीय पंचकोशी परिक्रमा शुरू हुई। पंचदशनाम जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से पंचकोशी परिक्रमा और प्रयागराज दर्शन यात्रा का शुभारंभ दत्तात्रेय सेवा समिति शिविर से किया गया। दत्तात्रेय शिविर में सबसे पहले परम्परा के मुताबिक साधु, संतों के लिए खिचड़ी भोज आयोजित किया गया। इसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण की अध्यक्ष और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने साधु, संतों का माला और शाल पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद कमिश्नर ने नारियल फोड़ कर पंचकोशी परिक्रमा का शुभारंभ किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और अखाडा परिषद के महामंत्री हरि गिरि महाराज के नेतृत्व में साधु, संत सबसे पहले संगम तट पर पहुंचे। जहां पर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तीर्थ पुरोहितों ने गंगा पूजन कराया। गंगा पूजन के साथ ही साधु संतों ने पंचकोशी परिक्रमा के साथ माघ मेले के भी सकुशल और निर्विघ्न संपन्न होने की मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से कामना की। जगदगुरू शंकराचार्य स्वामी नरेन्द्रानंद सरस्वती महराज ने सभी को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कमिश्नर प्रयागराज सौम्या अग्रवाल, मेला अधिकारी ऋषिराज और मेला एसपी नीरज पांडेय भी मौजूद रहे। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा है कि पंचकोशी परिक्रमा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं माघ मेला एसपी नीरज पांडेय ने कहा है कि जिन थाना क्षेत्रों से होकर पंचकोशी परिक्रमा जाएगी उन मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

स्वामी गोपालाचार्य महराज की भागवद कथा आठ से

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। माघ मेला के त्रिवेणी रोड, संगम लोवर चौराहे पर ऋषिकेश के जगदगुरू स्वामी कृष्णाचार्य महराज का शिविर लगा हुआ है। शिविर में स्वामी गोपालाचार्य महराज की श्रीमदभागवद कथा आठ जनवरी को सुबह नौ बजे से 12 बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक होगी। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 18 जनवरी से 22 जनवरी तक दोपहर दो बजे से शुरू होगा। संत सम्मेलन 22 जनवरी को दोपहर दो से शुरू होगा और बसंत पंचमी 23 जनवरी को सुबह नौ बजे से जगदगुरू स्वामी कृष्णाचार्य महराज का पटटोत्सव (जन्मोत्सव) शिविर में धूमधाम से मनाया जाएगा। शिविर के व्यवस्थापक मोहन पाण्डेय ने बताया कि पौष पूर्णिमा से अन्न क्षेत्र शुरू हो गया है जो माघी पूर्णिमा तक चलेगा।

25 वर्षों से बनी सरकारी नाली पर दबंगों ने किया कब्जा, जलनिकासी ठप

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। नगर निगम प्रयागराज के वार्ड संख्या-50 कटका (पूर्वी) अंतर्गत कटका चौराहा के दाहिनी ओर जोखू यादव मार्ग के अंदर स्थित 25 वर्ष पुरानी सरकारी नाली को दबंगई के बल पर पाटे जाने का गंभीर मामला सामने आया है।

आरोप है कि क्षेत्र निवासी राजकुमार यादव उर्फ बुल्ले पुत्र सूरज बली यादव उर्फ लाला ने अपने परिवार के साथ मिलकर दिनांक 04 जनवरी 2026 को उक्त सरकारी नाली को गिट्टी, बालू व सीमेंट डालकर पूरी तरह पाट दिया। नाली पाटे जाने से पूरे मोहल्ले की जलनिकासी व्यवस्था बाधित हो गई है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार यह नाली न केवल 25 वर्षों से अस्तित्व में है, बल्कि नगर निगम प्रयागराज द्वारा वर्ष 2023 में इसकी मरम्मत कराई गई थी तथा नाली के ऊपर पटिया भी डलवाई गई थी। नाली पाटे जाने के बाद उक्त पटिया को उखाड़कर पास में फेंक दिया गया है। मामले से संबंधित स्थल की जीपीएफ फोटो भी उपलब्ध कराई गई है।

मोहल्लेवासियों का आरोप है कि जब नाली पाटने का विरोध किया गया तो आरोपित और उनके परिजनों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। लोगों से कहा गया कि 'भाग जाओ, नहीं तो ज़िंदा नहीं बचोगे।' दबंग प्रवृत्ति के चलते क्षेत्रवासी भयभीत हैं और खुलकर सामने आने से कतरा रहे हैं।

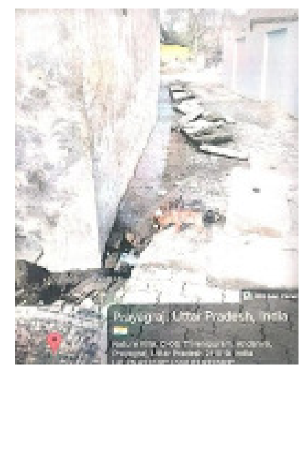

इतना ही नहीं, आरोप है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा अपने घर के पश्चिम दिशा में स्थित रेलवे की भूमि पर भी अवैध कब्जा कर उसे बेच दिया गया, जहां कई मकान बन चुके हैं और कई निर्माणाधीन हैं। स्थानीय स्तर पर इसकी जांच कराए जाने की मांग उठ रही है।

मोहल्लेवासियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि सरकारी नाली को तत्काल खुलवाया जाए तथा आरोपित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस न कर सके।

सम्पादकीय

जवाबदेही के बजाए दिया जा रहा मुआवजा, मंत्री और सरकार का रवैया अफसोसजनक

इंदौर में पेयजल दूषित होने की वजह से कई लोगों की मौत के बाद राहत के तौर पर सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा की गई, लेकिन सवाल है कि क्या कुछ रस्मी औपचारिकताएं पूरी करना इस समस्या का हल हो सकता है! सबसे जरूरी था कि इस घटना के बाद निचले स्तर के संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के समांतर शीर्ष स्तर पर बरती गई लापरवाही के लिए भी जिम्मेदारी तय की जाती। मगर ऐसा लगता है कि इसे किसी सामान्य हादसे की शक्ल में देखा जा रहा है। वरना क्या कारण है कि इतने गंभीर मामले के बाद भी सरकार के रवैये में एक अफसोसनाक उदासीनता दिख रही है।

इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय वहां के एक मंत्री सवालों को जिस तरह बेमानी बता रहे थे, उसमें एक विचित्र उपेक्षाभाव था। अव्वल तो पेयजल जैसी सबसे बुनियादी जरूरत के पूरी तरह सुरक्षित होने को लेकर सरकार अपनी ओर से सजग रहती, लेकिन इसके बजाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा है कि प्रभावित इलाके में पीने के पानी के अतिरिक्त टैंकर भेजे जाएं।

इस घटना से फिर यही जाहिर हुआ है कि महज हादसा या चूक मानी जाने वाली कई घटनाएं अक्सर अधिकारियों की अदूरदर्शिता, लंबे समय से बरती जाने वाली लापरवाही और कई बार जानबूझ कर की गई उपेक्षा का नतीजा होती हैं। इंदौर के जिस इलाके में पेयजल दूषित होने की घटना सामने आई, क्या ऐसा अचानक हो गया होगा? अगर फिलहाल आई खबरों पर ही भरोसा किया जाए कि पानी की आपूर्ति वाले पाइप में गंदे नाले का पानी मिल गया, तो इस पर निगरानी रखना किसकी जिम्मेदारी है? एक बार पेयजल की पाइप बिछा देने के बाद उसमें पानी आ रहा है या नहीं या फिर वह पीने के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है, इसकी नियमित जांच करने, गड़बड़ियों की निगरानी करने का दायित्व किस पर है?

अगर संबंधित महकमे में निचले स्तर पर तैनात कर्मचारी लापरवाही बरत रहे थे, तो इसका ध्यान रखना किसका काम था? इस गंभीर घटना के बाद सवाल उठने और कठघरे में खड़ा किए जाने के बाद जहां सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेकर सख्त संदेश देने वाली कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां उसके मंत्री संवेदनहीन, अवांछित और गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे थे। अफसोस की बात यह भी है कि इस समूचे मामले में केंद्र सरकार ने एक तरह से विचित्र चुप्पी साधे रखी और उसकी ओर से कुछ नहीं किया गया। जबकि पिछले कई वर्षों से स्वच्छता के लिए तमगा जीतने वाले इंदौर में दूषित पेयजल से जिस तरह की त्रासद घटना सामने आई, वैसे में पीड़ित परिवारों से लेकर देश भर के आम लोग यह उम्मीद करते हैं कि इसकी गंभीरता के मद्देनजर केंद्र सरकार दखल देगी।

दरअसल, ऐसे नाजुक मौकों पर सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि सरकार आम लोगों के प्रति संवेदनशील दिखे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने का भरोसा दे। मगर कम से कम इस मामले में सच यह है कि लोगों का सरकार पर से भरोसा बुरी तरह टूटा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि राष्ट्रीय स्तर पर 'हर घर नल जल' योजना के तहत सभी नागरिकों को पीने का स्वच्छ और शुद्ध पानी मुहैया कराने के दावे किए जाते रहे हैं। मगर पेयजल को लोगों तक पहुंचाने के रास्ते में अगर किसी भी वजह से ऐसी लापरवाही होती है कि उससे लोगों की जान पर खतरा आ जाए, तो ऐसे दावों को किस तरह देखा जाएगा।

1000 साल पुराने हमलों के बाद भी वैभव के साथ खड़ा है सोमनाथ मंदिर, देश को भी संकल्प की जरूरत

सोमनाथ... ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में, प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता हैष्ठ'सौराष्ट्रे सोमनाथं चष्ठयानि ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। शास्त्रों में ये भी कहा गया हैः

'सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत्?'

अर्थात सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। दुर्भाग्यवश, यही सोमनाथ, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्त्व रखता है क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था।

सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी, एक हजार वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साल 1026 के बाद समय-समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनःनिर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण सम्पन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे।

1026 में एक हजार वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण, वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। हर पंक्ति में क्रूरता के निशान मिलते हैं, ये ऐसा दुःख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इसका उस दौर में भारत पर और लोगों के मनोबल पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्त्व बहुत ज्यादा था। ये बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचता था। ये एक ऐसे समाज की प्रेरणा था जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी। हमारे समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर-दूर तक ले जाते थे।

सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है, ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। साल1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार-बार सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया।

यह हमारे लोगों और हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था। लेकिन हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर बार, पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनः जीवंत किया। महमूद गजनवी लूटकर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, हमारा विश्वास और प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं की भीतर सांस लेती रही। साल 1026 के हजार साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है, वो आज भी हमारी शक्ति का पुंज है।

ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस धरती पर जीवन पाया है, जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का पुण्य प्रयास किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सकें। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे, वो अनुभव उन्हें भीतर तक आंदोलित कर गया। 1897 में चेन्नई में दिए गए एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर आपको ज्ञान के अनगिनत पाठ सिखाएंगे। ये आपको किसी भी संख्या में पढ़ी गई पुस्तकों से अधिक हमारी सभ्यता की गहरी समझ देंगे। इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं, और सैकड़ों बार इनका पुनर्जागरण हुआ है। ये बार-बार नष्ट किए गए, और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए। पहले की तरह सशक्त। पहले की तरह जीवंत। यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है, मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा।'

ये सर्वविदित है कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। उन्होंने आगे बढ़कर इस दायित्व के लिए कदम बढ़ाया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे, और फिर जो हुआ, उसने एक नया इतिहास रच दिया

सोमनाथ मंदिर का कोई भी उल्लेख केएम मुंशी जी के योगदानों को याद किए बिना अधूरा है। उन्होंने उस समय सरदार पटेल का प्रभावी रूप से समर्थन किया था। सोमनाथ पर उनका कार्य, विशेष रूप से उनकी पुस्तक 'सोमनाथ, द श्राइन इटरनल', अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। जैसा कि मुंशी जी की पुस्तक के शीर्षक से स्पष्ट होता है, हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो आत्मा और विचारों की अमरता में अटूट विश्वास रखती है। हम विश्वास करते हैं- नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सोमनाथ का भौतिक ढांचा नष्ट हो गया, लेकिन उसकी चेतना अमर रही। इन्हीं विचारों ने हमें हर कालखंड में, हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने, मजबूत बनने और आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया है। इन्हीं मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प की वजह से आज भारत पर दुनिया की नजर है। दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। वह हमारे सृजनशील (इनोवेटिव) युवाओं में निवेश करना चाहती है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत और हमारे अनेक पर्व आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। योग और आयुर्वेद जैसे विषय पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। ये स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। अनादि काल से सोमनाथ जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ता आया है। सदियों पहले जैन परंपरा के आदरणीय मुनि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य यहां आए थे और कहा जाता है कि प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा, 'भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याः क्षयमुपगता यस्य।' अर्थात उस परम तत्त्व को नमन जिसमें सांसारिक बंधनों के बीज नष्ट हो चुके हैं। जिसमें राग और सभी विकार शांत हो गए हैं।"

आज भी दादा सोमनाथ के दर्शन से ऐसी ही अनुभूति होती है। मन में एक ठहराव आ जाता है, आत्मा को अंदर तक कुछ स्पर्श करता है, जो अलौकिक है, अव्यक्त है। वर्ष 1026 के पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जना करता है और तट को स्पर्श करती लहरें उसकी पूरी गाथा सुनाती हैं। उन लहरों की तरह सोमनाथ बार-बार उठता रहा है। अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है।

सोमनाथ हमें ये बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। ये वो स्वर है, जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए, इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। एक ऐसा भारत, जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। जय सोमनाथ!

सहानुभूति तक सीमित हो गई संवेदना, ठहर गया है सामाजिक आचरण

समकालीन समाज तेजी से बदल रहा है। हर दिन अखबारों और डिजिटल माध्यमों में पीड़ा, असमानता और संघर्ष की खबरें आम हो गई हैं। आदिवासी अंचलों में विस्थापन, शहरों की ओर बढ़ता पलायन, शिक्षा से बाहर होते बच्चे और महिलाओं के साथ होती हिंसा- ये अब केवल घटनाएं नहीं, बल्कि आंकड़ों में दर्ज सच्चाइयां हैं। इन पर हम दुख व्यक्त करते हैं, सहानुभूति जताते हैं, लेकिन हमारा सामाजिक आचरण अक्सर वहीं ठहर जाता है।

किसी के दुख को देखकर करुणा का भाव जागना समाज को असंवेदनशील होने से बचाता है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह भावना केवल शब्दों, बयानों और औपचारिक प्रतिक्रियाओं तक सीमित रह जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित सामाजिक और आर्थिक रपटें बताती हैं कि असमानता और वंचना आज भी व्यापक है, फिर भी अधिकांश मामलों में हमारी भूमिका केवल चिंता व्यक्त करने तक सिमट जाती है। असल में सहानुभूति हमें भावनात्मक संतोष देती है, पर व्यावहारिक जिम्मेदारी का बोध नहीं कराती।

आदिवासी समाज इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 फीसद हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है, लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों में उनकी हिस्सेदारी अनुपात से कहीं अधिक रही है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बड़े बांधों, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित लोगों में लगभग चालीस फीसद तक आदिवासी समुदायों से आते हैं। यह तथ्य केवल विस्थापन का नहीं, बल्कि संस्कृति, आजीविका और सामाजिक पहचान के टूटने का भी संकेत देता है। सहानुभूति के रूप में मुआवजे और पुनर्वास की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन समानुभूति तभी होगी, जब नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और विकास को उनके जीवन-संदर्भ से जोड़कर देखा जाए। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी यही अंतर स्पष्ट दिखाई देता है।

यूनिसेफ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जैसी संस्थाओं की रपटें बताती हैं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर अब भी चिंता का विषय है, विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में। सहानुभूति के तौर पर छात्रवृत्तियां, मध्याह्न भोजन और योजनाएं मौजूद हैं, पर समानुभूति तब सामने आती है जब शिक्षा व्यवस्था यह स्वीकार करती है कि भाषा, गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियां सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जब शिक्षक और व्यवस्था बच्चे की पृष्ठभूमि को समझकर अपनी पद्धति में बदलाव करते हैं, तभी शिक्षा वास्तव में समावेशी बनती है।

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बढ़ता पलायन भी हमारे सामाजिक आचरण की परीक्षा लेता है। करोड़ों लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़कर शहरों में अस्थायी या असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। शहरी अर्थव्यवस्था इन श्रमिकों पर निर्भर है, फिर भी सामाजिक व्यवहार में वे अक्सर अदृश्य रहते हैं। हम उनके श्रम का लाभ उठाते हैं, पर उनके आवास, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर उदासीन बने रहते हैं। यह उदासीनता सहानुभूति की सीमा को दर्शाती है, जहां समस्या को देखा तो जाता है, पर उसे अपना नहीं माना जाता।

डिजिटल युग ने संवेदनाओं को भी एक नए रूप में ढाल दिया है। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे से जुड़े आंकड़े, तस्वीरें और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। यह तथाकथित डिजिटल सहानुभूति हमें प्रतिक्रिया तो देती है, पर सहभागिता नहीं सिखाती। असल में केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति पर्याप्त नहीं, जब तक सामाजिक और मानवीय दृष्टि उसके साथ न चले। सामाजिक आचरण तब बदलता है, जब संवेदना औपचारिकता से निकलकर व्यवहार में उतरती है। जब नीति निर्माण में आंकड़ों के साथ मानवीय अनुभवों को महत्त्व दिया जाता है, जब योजनाएं बनाते समय जमीनी सच्चाइयों को समझा जाता है, तब सहानुभूति समानुभूति में बदलती है। जिटल युग ने संवेदनाओं को भी एक नए रूप में ढाल दिया है। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे से जुड़े आंकड़े, तस्वीरें और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। यह तथाकथित डिजिटल सहानुभूति हमें प्रतिक्रिया तो देती है, पर सहभागिता नहीं सिखाती।

ईरान के जेन-जेड प्रदर्शनकारियों से अमेरिकी सहानुभूति के वैश्विक मायने

ईरान के जेन-जेड प्रदर्शनकारियों से अमेरिकी सहानुभूति के वैश्विक मायने बड़े ही खतरनाक हैं। लिहाजा यदि समय रहते ही एशियाई देश नहीं चेते तो वे सब धीरे-धीरे अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतियों के सहज शिकार बन सकते हैं। पहले बंगलादेश, फिर नेपाल और अब ईरान में हुए जेन-जेड प्रदर्शन वाकई अमेरिकी डीप स्टेट की उन छिपी हुई मंशाओं को उजागर करते हैं, जिसका उद्देश्य चीन और रूस के सदाबहार मित्र भारत को कमजोर करना है क्योंकि ये दोनों अमेरिका की वैश्विक दादागिरी की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि पहले तो अमेरिका ने इन्हें यानी चीन-भारत को पटाकर और भारत-चीन को परस्पर उलझाकर अपने चिर शत्रु देश रूस को और अधिक कमजोर की कोशिशें की, लेकिन जब वो अपने नापाक इरादों में सफल नहीं हुआ तो इनके पड़ोस में 'भारत विरोध' को हवा दिलवानी शुरू कर दी। इसलिए बंगलादेश व नेपाल न सही, लेकिन ईरान में भारत, चीन और रूस को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और कथित लोकतंत्र के नाम पर अमेरिकी थानेदारी का कड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध करना चाहिए, अन्यथा अगला नम्बर अब उन्हीं का आएगा।

देखा जाए तो ईरान में रोजगार और बढ़ती महंगाई को लेकर बीते पांच दिनों से जारी जेन-जेड के विरोध प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। लिहाजा, ईरानी सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसमें अबतक सात प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और कइयों के घायल होने की पुष्टि हुई है। वहीं, इससे व्याकुल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 'एक्स' पर लिखा है कि, 'अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है तो हम बचाने को तैयार हैं।'

वैश्विक कूटनीतिज्ञों का मानना है कि अमेरिकी नेतृत्व द्वारा दिया गया उक्त बयान ईरान में लोकतंत्र की हिफाजत के बहाने वहां लगी आग में घी डालने जैसा है, जो निंदनीय भी है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंफ भी अब डीप स्टेट के समक्ष घुटने टेक चुके हैं और इसकी तथाकथित कारगुजारियों को बढ़ावा देने लगे हैं, जो वाकई दिलचस्प है।

हालांकि, इस अमेरिकी दुस्साहस पर पलटवार करते हुए ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा कि, 'ईरान की सुरक्षा रेड लाइन है।' ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने कहा कि- 'अमेरिका और इस्राइल प्रदर्शन भड़का रहे हैं। अमेरिकी दखल से अशांति फैल जाएगी, उन्हें अपने सैनिकों की फिक्र करनी चाहिए।' कहने का तातपर्य यह हुआ कि यदि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान उसके खाड़ी देशों और अरब देशों में स्थित सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। पिछले वर्ष वह ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान ऐसा कर भी चुका है, जिसके बाद घबराहट में अमेरिका ने उस युद्ध को मध्यस्थता करके बंद करवाया था।

स्वाभाविक सवाल है कि ईरानी प्रदर्शनकारियों के जिस तरह के उग्र विडियो सामने आए हैं, जहां प्रदर्शनकारी ईरान की सरकारी इमारतों पर पत्थरबाजी करते देखे गए, उसके दृष्टिगत ईरानी सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई करके अपने राष्ट्रीय धर्म का पालन किया है। अन्यथा बंगलादेश व नेपाल की तरह वो सुरक्षाकर्मी भी घुटने टेक सकते थे। हालांकि उन्होंने यह सख्ती दो तीन दिन प्रदर्शनकारियों को झेलने के बाद दिखाई है।

इसलिए डॉनल्ड ट्रंप का यह कहना कि, 'ईरान का रिवाज मारना है!', न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। उनकी यह टिप्पणी कि, 'अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद को आगे बढ़ने के लिए तैयार है', प्रथमदृष्टया ईरान के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है। इससे जाहिर है कि अब वो भी उस डीप स्टेट के हाथों खेलने को अभिशप्त हैं, जिसका विरोध उन्होंने खुद ही अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान किया था। लिहाजा स्वाभाविक सवाल है कि क्या अब्राहम परिवार में एका स्थापित करने की चाह रखने वाले डॉनल्ड ट्रंप अब ईरान को इस्लामिक देश नहीं मानते हैं और उसे पुनः पारसी देश बनाने की चाल चल रहे हैं, यक्ष प्रश्न है।

ऐसा इसलिए कि अमेरिकी डीप स्टेट एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो संघीय एजेंसियों जैसे सीआईए, एफबीआई और एनएसए के गुप्त नेटवर्क को संदर्भित करता है। यह कथित रूप से चुनी हुई सरकार के समानांतर सत्ता संचालित करता है। जहां तक डीप स्टेट की परिभाषा का सवाल है तो आपको पता होना चाहिए कि यह शब्द 1990 के दशक में तुर्की से उत्पन्न हुआ और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में लोकप्रिय हुआ। क्योंकि तब ट्रंप ने इसे रूस की जांच और अन्य विपत्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। सच कहूं तो यह नेटवर्क वित्तीय, औद्योगिक हितों के साथ मिलकर निर्वाचित नेताओं को प्रभावित करता है।

ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति इसे क्यों संरक्षण देते हैं? तो इसका माकूल जवाब यह आम व खास धारणा है कि कुछ प्रशासनों (जैसे-जो बाइडन प्रशासन के द्वारा) को डीप स्टेट का संरक्षण प्राप्त होता है क्योंकि यह विदेश नीति और खुफिया कार्यों में स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप जैसे नेता इसे अपना दुश्मन मानते आये हैं और इसका विरोध करते रहे हैं। यही वजह है कि वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप (2025 में पुनः शपथग्रहण के बाद) कहीं इसे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं शह देते नजर आ रहे हैं। इससे वह अपने ही उद्देश्य में विफल साबित हुए।

आपने देखा होगा कि भारत में विगत तीन पारियों से केंद्रीय सत्ता पर काबिज भाजपा ने भी डीप स्टेट पर मोदी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था, जबकि डीप स्टेट मुख्यतः षड्यंत्र सिद्धांत है। कई अमेरिकी सर्वे में वहां के आधे लोग इसके अस्तित्व में विश्वास करते हैं। कहना न होगा कि डीप स्टेट की अवधारणा मूल रूप से एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो गुप्त शक्तियों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है। इसका आधुनिक इतिहास तुर्की से जुड़ा है, जहां 1990 के दशक में 'डेरिन देवलेट' (गहरा राज्य) शब्द का इस्तेमाल सेना, खुफिया एजेंसियों और अपराधी तत्वों के गठजोड़ के लिए हुआ।

जहां तक इसके उद्भव की बात है तो इसका प्रारंभिक चरण तुर्की में 1990 के दशक के एक सड़क हादसे से लोकप्रिय हुआ, जिसमें एक राजनेता, पुलिस अधिकारी और माफिया डॉन की मौत हुई। इससे कथित गुप्त गठबंधन यानी डीप स्टेट की चर्चा शुरू हुई। फिर अमेरिका में ओबामा प्रशासन के दौरान इसका जिक्र बढ़ा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 से इसे मुख्यधारा में लाकर सीआईए और एफबीआई जैसी एजेंसियों को निशाना बनाया।

जहां तक अमेरिकी संदर्भ में इसके विकास की बात है तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में डीप स्टेट को रूस की जांच और अन्य घटनाओं से जोड़ा गया। 2017-18 के सर्वे में लगभग आधे अमेरिकियों ने इसके अस्तित्व में विश्वास जताया। कुछ सिद्धांतकार इसे रोथ्सचाइल्ड, रॉकफेलर जैसे वित्तीय समूहों से जोड़ते हैं, जो 18वीं सदी से बैंकिंग के माध्यम से प्रभाव डालते रहे।

जहां तक डीप स्टेट के वैश्विक प्रसार की बात है तो यह तुर्की से निकलकर यह मिस्र, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में फैला। भारत में भाजपा ने 2024 में इसे मोदी सरकार के खिलाफ साजिश से जोड़ा। हालांकि, कतिपय विद्वान इसे अतिशयोक्तिपूर्ण सिद्धांत मानते हैं क्योंकि वो खुद किसी न किसी रूप में डीप स्टेट से लाभान्वित हैं। वास्तव में डीप स्टेट एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो सरकारी, सैन्य, खुफिया एजेंसियों और कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग के गुप्त नेटवर्क को संदर्भित करता है। यह नेटवर्क लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के बाहर काम करता है और नीतियों को प्रभावित करने का दावा किया जाता है।

मसलन, डीप स्टेट शब्द तुर्की के 'डेरिन देवलेट' से लिया गया है, जो गैर-निर्वाचित तत्वों के समूह को दर्शाता है। यह समूह अपने विशेष हितों, जैसे सुरक्षा या आर्थिक एजेंडे, को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से सक्रिय रहता है। वहां का पेंटागन, हथियार निर्माता कंपनियां, नौकरशाही और वित्तीय अभिजात यानी बड़े कॉर्पोरेट्स, बैंकिंग समूह जैसे रॉकफेलर या रोथ्सचाइल्ड भी इससे जुड़े हुए हैं।

इतना ही नहीं, गूगल, फेसबुक जैसे टेक दिग्गज और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे एनजीओ भी इसके पार्ट समझे जाते हैं। नौकरशाह और पूर्व अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, खुफिया अधिकारी जो वैचारिक प्रतिबद्धताओं से प्रेरित रहते हैं, इसके अंग बन हैं। वहीं वहां के

वित्तीय परिवार जैसे रोथ्सचाइल्ड, रॉकफेलर जैसे समूह, जो बैंकिंग और परोपकार के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। वहां की सिविल सोसायटी यानी मीडिया, प्रोफेसर, कलाकार और एनजीओ कार्यकर्ता जो मानवाधिकार या पर्यावरण के नाम पर सक्रिय रहते हैं।

इसके संचालन का तरीका भी गजब है। ये समूह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बायपास कर शासन परिवर्तन या अस्थिरता पैदा करते हैं। भारत में इन्हें अर्बन नक्सल या राष्ट्रविरोधी इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। यह लोकतांत्रिक नियंत्रण से बाहर रहता है और निर्वाचित नेताओं को कमजोर करने का आरोप लगाया जाता है। हालांकि, कई विशेषज्ञ इसे अतिशयोक्तिपूर्ण सिद्धांत मानते हैं।

बताया जाता है कि अमेरिका के आर्थिक और कॉर्पोरेट हित डीप स्टेट के सिद्धांत में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जहां इन्हें गुप्त नेटवर्क का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ये हित सरकारी नीतियों को प्रभावित कर लाभ कमाते हैं। वहां से कॉर्पोरेट जुड़ाव रखने वाले यानी कॉर्पोरेट दिग्गज जैसे गूगल, फेसबुक और हथियार कंपनियां डेटा गोपनीयता, कराधान तथा बाजार विनियमन पर प्रभाव डालती हैं। ये शक्तिशाली इकाइयां खुफिया एजेंसियों के साथ साझेदारी कर आर्थिक नीतियों को आकार देती हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे संगठन शासन परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं।

इसका आर्थिक प्रभाव निर्णायक होता है। वहां के वित्तीय परिवार जैसे रोथ्सचाइल्ड और रॉकफेलर बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण के माध्यम से प्रमुख घटनाओं जैसे एशियाई वित्तीय संकट को प्रभावित करते हैं। ये समूह मुक्त बाजार, व्यापार वार्ता और शॉक थेरेपी जैसी नीतियों को प्रोत्साहित कर विकासशील देशों में बाजार पहुंच सुनिश्चित करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे उदाहरण स्टॉक बाजार अस्थिरता पैदा करते हैं। ये परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। ये हित सैन्य-औद्योगिक परिसर के साथ मिलकर युद्ध अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, जहां कॉर्पोरेट फंडिंग राजनीतिक प्रभाव खरीदती है। भारत जैसे देशों में एनजीओ वित्तपोषण कोयला परियोजनाओं का विरोध करता है, जो जीडीपी वृद्धि को 2-3इ नुकसान पहुंचाता है।

इसलिए इनके कारनामों से शेष दुनिया के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गरीब व विकासशील देशों के धनलोलुप नेता व चतुरसुजान अब इनके अंग बन चुके हैं। भारत, चीन व रूस में भी इनकी अच्छी खासी तादात होने की अटकलें हैं।

डीएम व एसपी ने घोसिया धान क्रय केंद्र का किया निरीक्षण, किसानों से की बातचीत

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने सोमवार को घोसिया स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र वि-पैक्स तथा घोसिया किसान सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने केंद्र पर मौजूद किसानों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और धान क्रय प्रक्रिया की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने मौके पर धान विक्रय करने आए दो किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सभी पात्र किसानों को मिलेगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपना धान केवल सरकारी धान क्रय केंद्रों पर ही विक्रय करें, जिससे उन्हें 2369 रुपये प्रति कुंतल की दर से समर्थन मूल्य का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

निरीक्षण के दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी शिशिर कुमार ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जनपद में कुल 30 धान क्रय केंद्र संचालित हैं, जिनमें 15 खाद्य विपणन विभाग, 14 पीसीएफ तथा एक भारतीय खाद्य निगम का केंद्र शामिल है। जनपद का धान क्रय लक्ष्य 35 हजार मीट्रिक टन निर्धारित है। वहीं क्रय केंद्र प्रभारी ने बताया कि घोसिया केंद्र पर अब तक 2046

कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। केंद्र पर यूरिया, डीएपी, एनपीएस व पोटाश उपलब्ध हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि धान क्रय नीति का पूर्ण पालन किया जाए और किसी भी स्थिति में किसानों को क्रय केंद्र से वापस न किया जाए। बिचौलियों के माध्यम से खरीद की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन में तेजी लाने और सभी क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण कराने के निर्देश भी दिए गए।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी औराई श्याममणि त्रिपाठी, एआर कोऑपरेटिव रामप्रकाश, जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

भीषण शीतलहरी से गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों के बचाव हेतु डीएम, एसपी ने किया निरीक्षण, दिए निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जनपद में शीत ऋतु के दृष्टिगत संरक्षित गोवंशों को ठंड से बचाव हेतु किए गए समुचित प्रबंध का जिलाधिकारी शैलेष कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल चीनी मिल औराई का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित सभी गो आश्रय संचालकों को निर्देश दिया कि निराषित गोचर को ठंड से बचाने हेतु पर्यात मात्रा में पौष्टिक आहार (भूसा, पराली, हरा चारा, दाना, गुड इत्यादि) जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाईड्रेट उपलब्ध हो एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। गोवशं को ठंड में बचाव हेतु गो आश्रय स्थलों में शीत लहर के प्रभाव को रोकने के लिए त्रिपाल, बोरा इत्यादि का प्रयोग किया जाए तथा वृद्ध, आशक्त व नवजात गोवंश के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

प्रत्येक गो आश्रय स्थलों पर निरंतर प्रभावी निगरानी करते हुए शेड को विधिवत कवर कराया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर जनपद स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध अनुपयोगी बोरा, टाट आदि को गो आश्रय स्थलों को उपलब्ध करा‌कर प्रयोग में लिया जाए।

गो आश्रय स्थलों की समुचित साफ़ सफाई सुनिश्चित कराई जाए। आश्रय स्थलों में पानी, गोबर, गोमूत्र आदि की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए और विछावन के रूप में पराली का उपयोग किया जाए तथा समय समय पर बिछावन को बदला जाना अति

आवश्यक है।

किसी भी स्थिति में रात्रि के समय गोवंश खुले स्थान पर न रहे और दिन में गोवंश को पर्याप्त धूप में रखा जाए। गो आश्रय स्थलों से संबद्ध/चिन्हित कब्जा मुक्त सिंचित चारागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन की व्यवस्था किया जाए।

उपस्थित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ ए के सचान ने बताया कि इस गो आश्रय स्थल में 517 गोवंश है जिनके देख रेख हेतु 11 केयर टेकर रखे गए हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि छोटे व कमजोर पशुओं के लिए अलग टीनशेड की व्यवस्था किया जाए तथा सभी पशुओं का शत प्रतिशत ईयर टैकिंग सुनिश्चित हो।

निरीक्षण में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, उप जिलाधिकारी औराई श्याम मणि त्रिपाठी, बीडीओ दिलीप कुमार आदि उपस्थित रहे।

बीडा प्राधिकरण ने सरोंई में अवैध लेआउट पर की ध्वस्तीकरण कार्रवाई

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। बीडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र अंतर्गत मौजा सरौई, तहसील व जिला भदोही में अनधिकृत रूप से विकसित किए गए भू-विन्यास (लेआउट) के खिलाफ सोमवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जिलाधिकारी भदोही एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बीडा के आदेश पर नामित मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी (न्यायिक), भदोही के नेतृत्व में की गई।

प्राधिकरण के अनुसार गाटा संख्या 281 में लगभग 3600 वर्गमीटर क्षेत्र में मो. शादाब व अबुकैफ पुत्रगण इस्तियाक अहमद, गाटा संख्या 162 में लगभग 2100 वर्गमीटर क्षेत्र में शमशेर अली, नसीम अहमद, मुबारक अली व मासूम अली पुत्रगण वजीर तथा गाटा संख्या 148 में लगभग 3500 वर्गमीटर क्षेत्र में कमलधर व सुंदरलाल द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध लेआउट विकसित किया गया था। बीडा द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 9 व 10 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया गया था, साथ ही सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया, लेकिन इसके बावजूद लेआउट को प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया।

इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बीडा ने आमजन से अपील की है कि प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी प्रकार का निर्माण न करें और किसी भी भूखंड की खरीद से पूर्व संबंधित लेआउट की स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सपा की मासिक बैठकें संपन्न

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। समाजवादी पार्टी जनपद भदोही के जिला कार्यालय ज्ञानपुर के तत्वावधान में जनपद की तीनों विधानसभा भदोही, ज्ञानपुर एवं औराई में मासिक बैठकें सफलतापूर्वक संपन्न हुईं। भदोही विधानसभा की बैठक पचभैया में विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव की अध्यक्षता में, ज्ञानपुर विधानसभा की बैठक गोसाई बाजार में लालचंद बिंद की अध्यक्षता में तथा औराई विधानसभा की बैठक लक्ष्मणिया में विधानसभा अध्यक्ष केशनारायण यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठकों में आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा के साथ-साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने और जनसंपर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के मुख्य अतिथि भदोही विधायक जाहिद बेग ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज तक प्रेम, दया और अपनापन लेकर पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जनता अपमान और पीड़ा झेल रही है, ऐसे में समाजवादी कार्यकर्ताओं को सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा।

विधायक ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उनके नाम अनिवार्य रूप से जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश ने विकास की नई दिशा देखी थी और अब एक बार फिर उसी ताकत को संगठित करने का समय है। बैठक में भदोही विधानसभा से दीपनारायण भारती, हृदय नारायण प्रजापति, सुरेश साहू, परमानंद मौर्य, अच्छे सरोज, प्रमोद, सुरेश, मिल्लू, सुनील, सौरभ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

तहसील औराई में डीएम व एसपी ने सुनी फरियादियों की शिकायतें

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। शासन के निर्देशानुसार जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से नववर्ष 2026 का पहला सम्पूर्ण समाधान दिवस जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित किया गया। तहसील औराई में जिलाधिकारी शैलेष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने अधिकारियों के साथ उपस्थित रहकर फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संतोष कुमार चक, उप जिलाधिकारी औराई श्याममणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में तहसील औराई में कुल 48 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 10 मामलों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से समय-सीमा में समाधान के निर्देश दिए गए। अधिकांश शिकायतें भूमि पैमाइश व राजस्व विवाद से संबंधित रहीं। डीएम ने निर्देशित किया कि किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने राजस्व से जुड़े मामलों में एक सप्ताह के भीतर संयुक्त टीम द्वारा जांच कर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बार-बार आने वाले विवादों की सूची बनाकर प्रभावी कार्यवाही की जाए।

गलत खाते में गई 9, 994 रुपये की रकम साइबर सेल ने कराई वापस

भदोही। पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में साइबर हेल्प डेस्क थाना ज्ञानपुर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए त्रुटिवश गलत खाते में स्थानांतरित हुई 9, 994 रुपये की धनराशि को पीड़ित के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दिया। थाना ज्ञानपुर निवासी सत्येन्द्र श्रीवास्तव द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि नंबर त्रुटि के कारण उनके खाते से धनराशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चली गई थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए साइबर हेल्प डेस्क द्वारा संबंधित पक्ष से तत्काल समन्वय स्थापित किया गया, जिसके बाद पूरी धनराशि सुरक्षित रूप से वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने भदोही पुलिस एवं साइबर टीम की तत्परता की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग की सघन कार्रवाई

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। शासन के निर्देश तथा जिलाधिकारी शैलेष कुमार के आदेश के क्रम में जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी अरुण कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 रजनीश कुमार पाण्डेय, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 रोहित कुमार व आबकारी निरीक्षक औराई अनिल कुमार सूर्यभान द्वारा मय स्टाफ द्वारा औराई व केवटाही स्थित विभिन्न ईंट-भट्ठों पर सघन दबिश दी गई। दबिश के दौरान अवैध मदिरा के निर्माण अथवा संग्रहण से संबंधित गतिविधियों की गहन जांच की गई। निरीक्षण में कोई अवैध गतिविधि नहीं पाई गई, तथापि संबंधित व्यक्तियों को भविष्य

में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में संलिप्त न होने की कड़ी चेतावनी दी गई।

इसके उपरांत लालानगर टोल प्लाजा पर वाहनों की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान वाहनों की चेकिंग कर मदिरा के अवैध परिवहन की संभावना को परखा गया। तलाशी अभियान के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त कंपोजिट शॉप उगापुर, देसी शराब दुकान भरतपुर (औराई) व केवटाही का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से स्कैनिंग कर बिक्री व्यवस्था की जांच की गई। उपलब्ध मदिरा स्टॉक का मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया तथा क्यूआर कोड के माध्यम से स्टॉक का मिलान किया गया, जो नियमानुसार सही पाया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता को शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप ही दुकान संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि जनपद में अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान आगे भी इसी प्रकार सख्ती के साथ जारी रहेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आमजन से भी अपील की गई है कि अवैध मदिरा से संबंधित किसी भी सूचना को तत्काल प्रशासन अथवा आबकारी विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

खेतलपुर हादसे के पीड़ित परिवार से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल

प्रशासन से सहायता की मांग की

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। औराई विकास खण्ड के विसापुर न्याय पंचायत अंतर्गत ग्राम सभा खेतलपुर में 12 दिसंबर को ट्रैक्टर की चपेट में आकर हुई सुजीत कुमार पटेल की दर्दनाक मृत्यु के मामले में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडेय एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता एवं न्याय दिलाए जाने की मांग की। इसके उपरांत उप जिलाधिकारी, औराई को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई।

इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे में शासन-प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में ब्लॉक अध्यक्ष शिवपूजन मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष दीनानाथ दुबे, जिला महासचिव अवधेश कुमार पाठक, संजय जायसवाल, धर्मेंद्र कुमार पटेल सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भदोही की तीनों तहसीलों में जागरूकता कार्यक्रम

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। महिला कल्याण विभाग द्वारा जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री शत्रुघ्न कनोजिया के मार्गदर्शन में सोमवार को तहसील भदोही, औराई व ज्ञानपुर में बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक एवं कठपुतली के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों पर प्रभावी संदेश दिया गया।

चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास को बाधित करता है और उनका भविष्य अंधकारमय बना देता है। बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दो वर्ष तक का कठोर कारावास या दोनों का प्रावधान है। टीम ने स्पष्ट किया कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई। साथ ही महिला कल्याण विभाग की टीम द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, 181 महिला हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, संबंधित अधिकारी तथा बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित रहे।

भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के राष्ट्रीय सचिव डॉ सुमित नागर ने किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

मंत्र भारत संवाददाता

मंडी धनौरा। सोनभद्र जनपद में किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के तत्वावधान में एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। यह कार्यक्रम पन्ना औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं सोनभद्र क्षेत्र के किसानों की चकबंदी, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, बिजली और प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आयोजित हुआ।

राष्ट्रीय सचिव सुमित कुमार नगर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन धनौरा उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को सौंपा।

किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में यह लंबे समय से औद्योगिक परियोजनाओं के कारण किसानों का शोषण हो रहा है, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं–

यमुना एक्सप्रेस-वे एवं औद्योगिक परियोजनाओं में अधिग्रहीत भूमि का शेष एवं अतिरिक्त मुआवजा तत्काल वितरित किया जाए।

नए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित किसानों को 20 प्रतिशत विकसित भूमि दी जाए।

गौतम बुद्ध नगर सहित अन्य जिलों की तरह सोनभद्र जिले में भी सर्किल रेट बढ़ाया जाए।

जिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें वर्तमान दरों पर मुआवजा दिया जाए तथा महंगाई के अनुसार मुआवजा राशि में वृद्धि की जाए।

जिन क्षेत्रों में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, वहां पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए।

चकबंदी के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

बिजली उपभोक्ताओं की सहमति के बिना जबरन स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं।

बिजली का निजीकरण बंद किया जाए।

बिजली कटौती पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए।

औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित क्रशर प्लांट एवं फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण से किसानों व आम जनता को राहत दिलाई जाए।

मानकों के विपरीत चल रहे क्रशर प्लांट व फैक्ट्रियों को तत्काल बंद कर उनके मालिकों एवं संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

अवैध रूप से संचालित प्लांटों की जांच कर उन्हें सील किया जाए। किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो संगठन आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव डॉ सुमित कुमार नागर, जयसिंह, जयविंद सिंह, आनंद कुमार, अनुराग, गौरव कुमार, दीपू चौहान, सतनाम सरदार, संतोष देवी, सुभाष चंद्र यादव, डॉ यतन सिंह, जितेंद्र सिंह, अमन, रवि कुमार, हिमांशु, जितेंद्र, नीरज कुमार, वंश, अर्जुन , जितेंद्र , भूपेंद्र सिंह, कोशिंदर सिंह, सोनू , अशोककुमार, अभय कुमार चौहान, नीरज यादव आदि मौजूद रहे।

यूपी पुलिस भर्ती में योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का ऐलान

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

हम आपको बता दें कि सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत कुल 32, 679 पदों को भरे जाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु शिथिलीकरण एक बार के लिए प्रदान किया जाएगा।

योगी सरकार द्वारा यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के आलोक में लिया गया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। देखा जाये तो योगी सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझती है और समाधान के लिए ठोस फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।

हम आपको यह भी बता दें कि साल 2025 के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं को 2026 का बड़ा तोहफा देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी इस अधिसूचना ने साफ संकेत दिया था कि योगी सरकार में रोजगार केवल घोषणा नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन चुका है। भर्ती बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को बोर्ड की वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ओटीआर के जरिए एक बार पंजीकरण कराने के बाद अभ्यर्थियों को बार-बार दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी।

'भगवान राम के लिए त्याग दिया था सीएम पद'

कल्याण सिंह की जयंती पर बोले मुख्यमंत्री योगी, पूर्व सीएम को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी जयंती पर याद करते हुए सोमवार को कहा कि राम भक्तों और संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी सत्ता का बलिदान करने वाले सिंह का कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 94वीं जयंती के अवसर पर यहां आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कहा कि जब उनकी सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश की गयी और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा तो सिंह ने राम भक्तों और संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रभु राम के प्रति अपनी सत्ता का बलिदान देने में कोई संकोच नहीं किया।

उन्होंने कहा, ''उनकी सरकार गयी, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने (कल्याण सिंह ने) सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर भगवान राम के प्रति, अपने कर्तव्यों का निर्वहन में तनिक भी देर नहीं लगायी।'' मुख्यमंत्री ने कहा

कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पहले मुख्यमंत्री थे।'' वर्ष 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी तब यहां अव्यवस्था, अराजकता और गुंडागर्दी थी। आतंकवादी गतिविधियां सिर उठा रही थीं।

शासन की योजनाओं का लाभ गांव और गरीबों को, किसानों, नौजवानों और महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक ओर अराजकता और कुव्यवस्था थी वहीं, दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए हिंदू समाज छटपटा रहा था। उन स्थितियों में बाबूजी (कल्याण सिंह) ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली।'' उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में जब कार्य शुरू किया तो कुछ ही महीनों में लोगों के मन में यह विश्वास पैदा होने लगा कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चलकर विकास के एक नए सोपान को जोड़ेगा।

आदित्यनाथ ने कहा, ''उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्रद्धेय बाबूजी का कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। आज यही कारण है कि हर भारतवासी बाबूजी को इस रूप में याद करता है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा और आजीवन उसे अपने जीवन का मंत्र बनाकर लगातार कार्य करते रहे। कल्याण सिंह की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा, ''आज वह हमारे बीच नहीं है लेकिन एक विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और राज्यपाल के रूप में भी उनकी सेवाएं सदैव पूरे देशवासियों के लिए अविस्मरणीय रहेंगी।''

आईपीएल पर बयान देना पड़ा भारी!

संगीत सोम को बांग्लादेशी नंबरों से जान से मारने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

लखनऊ **(एजेंसी)**। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और सांसद संगीत सोम को जान से मारने की धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। सांसद संगीत सोम ने बताया कि उन्हें बांग्लादेश के नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। यह कॉल्स आज सुबह से लगातार मिल रहे हैं, जिनमें उन्हें जान से मारने की चेतावनी दी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, ये धमकी भरे फोन कॉल्स उस बयान के बाद आने लगे हैं, जिसमें संगीत सोम ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के फैसले की सराहना की थी। संगीत सोम ने इस फैसले को भारत के हिंदुओं और सनातनियों की जीत बताया था।

सांसद संगीत सोम ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, 'भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।' उन्होंने आगे बताया कि इस बयान के बाद से ही उन्हें विदेश, खासकर बांग्लादेश के नंबरों से धमकी भरे कॉल्स मिल रहे हैं।

धमकियों की गंभीरता को देखते हुए संगीत सोम ने कहा कि वह जल्द ही पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। पुलिस भी पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और शिकायत मिलने के बाद कॉल डिटेल्स व नंबरों की जांच की जाएगी।

सांसद के बयान और उसके बाद मिली धमकियों को लेकर राजनीतिक और खेल जगत में भी चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ आईपीएल और विदेशी खिलाड़ियों को लेकर बहस चल रही है, वहीं दूसरी ओर किसी सांसद को विदेशी नंबरों से धमकी मिलना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मुद्दा माना जा रहा है।

दो दोस्तों के सिर धड़ से कटकर 50 मीटर दूर गिरे! 70 की स्पीड से बाइक ट्रक से टकराई और गर्दन के हिस्से छिटककर रोड पर आए

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर क्षेत्र स्थित गंभीरपुर बाजार में हुए एक भीषण हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मृतकों के सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरे। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि रविवार की रात करीब नौ बजे

ठेकमा से आजमगढ़ की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवारों को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों के सिर धड़ से अलग हो गये और उनके गर्दन के हिस्से लगभग 50 मीटर दूर जा गिरे। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान पूर्व ग्राम प्रधान संतोष यादव उर्फ गुड्डू और उसके मित्र संदीप यादव के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई तथा आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा।

शादी के बाद खुला पति के 'गंजा' होने का राज, महिला ने दर्ज कराया मुकदमा

लखनऊ **(एजेंसी)**। नोएडा के बिसरख क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने शादी के बाद पति के गंजा होने की बात पता चलने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, महिला ने पति के अलावा ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर पति संयम जैन, ससुर संजय जैन, सास सुषमा जैन, जीजा कुणाल जैन और मामा हेमंत जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गौर सिटी एवेन्यू-एक निवासी लविका गुप्ता ने रविवार को शिकायत दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसकी शादी 16 जनवरी 2024 को दिल्ली के राणा प्रताप बाग निवासी संयम जैन से हुई थी। उन्होंने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि शादी से पहले कई अहम तथ्यों को उनसे छिपाया गया।

सिंह ने कहा, ''महिला का आरोप है कि उनके पति पूरी तरह गंजे हैं और नकली 'हेयर पैच' (कृत्रिम बाल) का इस्तेमाल करते हैं, जबकि विवाह के समय बताया गया था कि

उनके घने बाल हैं।'' पुलिस के मुताबिक, महिला ने पति की शैक्षिक योग्यता और आय के बारे में भी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि शादी के बाद से ही पति उसे ब्लैकमेल करता रहा और मोबाइल फोन से निजी तस्वीरें निकालकर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देता था। थाना प्रभारी ने बताया, ''महिला ने विदेश यात्रा के दौरान पति द्वारा मारपीट किए जाने और थाईलैंड से भारत लौटते समय गांजा लाने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया है।'' पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।

सिंधु के जल पर पाकिस्तान को लगा नया झटका चिनाब नदी जलविद्युत परियोजना आगे बढ़ायेगा भारत

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चिनाब बेसिन की जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा की है और सावलकोट परियोजना से 800 मेगावॉट बिजली उत्पादन को प्राथमिक लक्ष्य घोषित किया है। यह साफ संकेत है कि भारत अब अपने प्राकृतिक संसाधनों को लेकर किसी भी तरह की हिचक नहीं रखता। हम आपको बता दें कि अपने दौरे के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा विकसित सावलकोट परियोजना से 800 मेगावॉट बिजली सृजन को सुनिश्चित करने की दिशा में स्पष्ट निर्देश दिए। चिनाब नदी पर स्थित यह परियोजना जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में उभर रही है, तथा इसका लक्ष्य न केवल विद्युत उत्पादन को बढ़ाना है बल्कि क्षेत्र की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी पूर्ण रूप से सुदृढ़ करना है।

हम आपको बता दें कि खट्टर ने समीक्षा की प्रक्रिया में एनएचपीसी द्वारा चलाये जा रहे अन्य प्रोजेक्टों, जैसे कि सेलाल पावर प्रोजेक्ट और रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी गौर किया। मंत्री ने रैटल परियोजना के डैम कंक्रीटिंग कार्य का शिलान्यास

किया और उन्होंने इंजीनियरों से समयबद्ध और गुणवत्ता नियंत्रित तरीके से कार्य पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही, सेलाल परियोजना में जमा गई तलछट को हटाने के लिये भी उन्होंने अधिकारियों को तीव्रता से काम करने के निर्देश दिए, ताकि जल भंडारण क्षमता अधिकतम हो सके और पानी का पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सके।

खट्टर ने यह स्पष्ट किया कि इन विद्युत परियोजनाओं के लिये पाकिस्तान की कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सिंधु जल संधि (1960) को स्थगित रखे जाने का हवाला देते हुए कहा कि अब भारत पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग अपने लोगों, अपने उद्योगों और अपनी भूराजनीतिक मजबूती के लिये करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं में किसी भी अवैध तत्व या ओवर ग्राउंड वर्कर को शामिल नहीं होने दिया जायेगा और सभी गतिविधियाँ कानूनी शासन और राष्ट्रीय हित के अनुरूप होंगी। बाइट।

देखा जाये तो जम्मू और कश्मीर में बड़े जल विद्युत प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का अर्थ है चीन और पाकिस्तान जैसी पड़ोसी शक्तियों के साथ भौगोलिक संतुलन बनाए रखना और अपनी जल-संरचना को ऐसे मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करना, जिससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो, बल्कि संभावित राजनीतिक प्रतिकूलताओं का सामना करने की क्षमता भी बढ़े।

देखा जाये तो सावलकोट, रैटल और सेलाल जैसे प्रोजेक्ट केवल बिजली उत्पादन मशीनें नहीं हैं; वे चिनाब नदी के जल भंडारण, नियंत्रण और उपयोग के अत्याधुनिक अवसंरचना केन्द्र हैं। पिछले साल तक सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान के लिये आरक्षित थीं, परंतु वर्तमान नीतिगत बदलाव के साथ भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब नदियों के पानी का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित के लिये करेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दुश्मनों को ललकार भारतीय तटरक्षक बल से टकराने की हिम्मत मत करना

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने देश की तटरेखा को शत्रुओं के लिए अछूत बना दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तटरक्षक बल ने शत्रुओं के मन में ऐसा भय पैदा कर दिया है कि यदि कोई सीमा की ओर देखने की भी हिम्मत करेगा, तो तटरक्षक बल उसे नहीं छोड़ेगा। आईसीजी के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र प्रताप' के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि हमारे तटरक्षक बल ने हमारे शत्रुओं के मन में ऐसा भय पैदा कर दिया है कि यदि कोई हमारी सीमा की ओर देखने की भी हिम्मत करेगा, तो तटरक्षक बल उसे ऐसा करने की स्थिति में नहीं छोड़ेगा।

रक्षा मंत्री ने कहा कि 'समुद्र प्रताप' का शुभारंभ देश की व्यापक समुद्री दृष्टि से जुड़ा है, जो यह मानती है कि समुद्री संसाधन किसी एक राष्ट्र की संपत्ति नहीं बल्कि मानवता की साझा विरासत हैं। उन्होंने कहा कि जब विरासत साझा होती है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी साझा होती है। यही कारण है कि भारत आज शांति,

स्थिरता और पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है।

भारत को एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, 'ऐसे समय में जब दुनिया वैश्विक समुद्री अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, भारत ने बार-बार यह साबित किया है कि वह न केवल अपने हितों की रक्षा करता है, बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। साथ मिलकर आगे बढ़ने का यही समावेशी दृष्टिकोण भारत को एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति बनाता है।' रक्षा मंत्री ने कहा, 'हमें समुद्री शासन के क्षेत्र में मानदंड निर्धारित करने होंगे, क्षमता निर्माण पहलों को मजबूत करना होगा और सहयोगात्मक ढांचों को आगे बढ़ाना होगा। भारतीय तटरक्षक बल को अपने परिचालन सिद्धांतों, संस्थागत प्रथाओं और तकनीकी नवाचारों को ऐसे उच्च मानकों तक पहुंचाना होगा कि उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्व स्तर पर अनुसरण किया जाए।'

उन्होंने आगे कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय तटरक्षक बल ने खुद को क्षेत्रीय मानक स्थापित करने वाले के रूप में स्थापित किया है। अब समय आ गया है कि इस भूमिका को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाया जाए और वैश्विक नेतृत्व की ओर निर्णायक रूप से कदम बढ़ाया जाए।' रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे दो प्रदूषण नियंत्रण पोतों (पीसीवी) की श्रृंखला में पहले पोत, भारतीय तटरक्षक पोत (आईसीजीएस) 'समुद्र प्रताप' को कमीशन किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उपस्थित थे।

मतदाता सूची पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा कहा- ममता के 'फर्जी वोट' का खेल अब खत्म

कोलकाता **(एजेंसी)**। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चुनौती दी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की आलोचना का कड़ा खंडन किया। उन्होंने एक्स पर एक संदेश साझा किया। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त,ॅईसीआईएसवीईईपी ज्ञानेश कुमार को पत्र भेजकर ममता बनर्जी के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के बारे में फैलाए गए झूठे दावों और इसे रोकने की उनकी नवीनतम अपील का खंडन किया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बारे में उनकी तथाकथित 'चिंताएँ' सरासर मनगढ़ंत हैं। वास्तव में, चुनाव आयोग की यह मुहिम टीएमसी के गंदे रहस्यों को उजागर कर रही हैः फर्जी मतदाता, मृत नेताओं के भूत और अवैध घुसपैठिए जिन्हें उन्होंने वर्षों से चुनाव में धांधली करने के लिए संरक्षण दिया है। अधिकारी ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ममता बनर्जी घबरा रही हैं क्योंकि एसआईआर उनके 2026 के सपनों के लिए एक बड़ा झटका है। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन और साफ करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण का संचालन कर रहा है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। यह विवाद आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य नेतृत्व और केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है। इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया था। 3 जनवरी को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने आईटी सिस्टम का दुरुपयोग किया और दावा किया कि मतदाताओं के नाम बिना उचित अनुमति के बैकएंड से हटा दिए गए थे।

खालिद को जमानत न देना और राम-रहीम को बार-बार पेरोल देना न्याय का मखौल है : महबूबा

श्रीनगर **(एजेंसी)**। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद को उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करना ''न्याय का मखौल'' है, जबकि बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दी जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया लेकिन ''भागीदारी के स्तर के क्रम'' का हवाला देते हुए पांच अन्य को जमानत दे दी

और कहा कि मामले में सभी आरोपी एक ही पायदान पर नहीं हैं।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि खालिद और इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। महबूबा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''न्याय का कैसा मखौल है! एक तरफ गुरमीत सिंह, जिसे बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया है, उसको बार-बार पैरोल मिल रही है। दूसरी तरफ उमर खालिद, जो केवल आरोपी है और जिसके खिलाफ अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, पांच साल से अधिक समय से जेल में है और आज उच्चतम न्यायालय ने भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। अन्याय के बोझ तले न्याय का तराजू टूट रहा है।'' उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम की चादर चढ़ाने का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सर्वोच्च न्यायालय ने अजमेर स्थित 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री द्वारा राज्य प्रायोजित औपचारिक सम्मान या चादर चढ़ाने की प्रथा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि चूंकि चादर चढ़ाई जा चुकी है, इसलिए यह मुद्दा निरर्थक हो गया है। पीठ ने यह भी कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर न्यायालय निर्णय ले सके। याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, को वार्षिक उर्स समारोह के तहत अजमेर दरगाह पर चादर जैसे औपचारिक सम्मान अर्पित करने से रोकने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ऐसे कृत्य जनता की इच्छा, राष्ट्रीय संप्रभुता और भारतीय संविधान के मूल्यों के विपरीत हैं।

अजमेर शरीफ दरगाह पर औपचारिक 'चादर' चढ़ाने की परंपरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में शुरू की थी और बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी इसका पालन किया। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है। जनहित याचिका में केंद्र सरकार द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिए गए 'राज्य-प्रायोजित औपचारिक सम्मान, आधिकारिक संरक्षण और प्रतीकात्मक मान्यता' को चुनौती दी गई है। ऐतिहासिक अभिलेखों का

हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमणों के दौरान भारत आए थे और विदेशी विजय और धर्मांतरण अभियानों से जुड़े थे, जबकि उनकी दरगाह को संस्थागत रूप बहुत बाद में मिला।

ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती उन विदेशी आक्रमणों से जुड़े थे जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर विजय प्राप्त की और स्थानीय आबादी का बड़े पैमाने पर दमन और धर्मांतरण किया। ये कृत्य भारत की संप्रभुता, गरिमा और सभ्यतागत मूल्यों के बिल्कुल विपरीत थे। ऐसे व्यक्ति को औपचारिक श्रद्धांजलि अर्पित करना संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय अखंडता का हनन है और जनता की इच्छा की अवहेलना है।

दिग्गज ऑलराउंडर ने भारत की अगली कप्तान की भविष्यवाणी की

मंधाना की जगह जोमिमा रोड्रिग्स पर दिखाया भरोसा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत की ऐतिहासिक महिला विश्व कप 2025 जीत के बाद अब चर्चा का केंद्र टीम का भविष्य और नेतृत्व है। मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर 36 वर्ष की हो चुकी हैं और उनके शानदार करियर के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही उत्तराधिकारी की खोज तेज हो गई है। जहां स्मृति मंधाना को लंबे समय से अगला कप्तान माना जा रहा था, वहीं दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज ऑलराउंडर मैरिज़ेन कैप ने एक अलग नाम आगे बढ़ाकर बहस को नया मोड़ दे दिया है। उनका मानना है कि भारत को ऐसा लीडर चाहिए जो टीम को जोड़कर रख सके।

विश्व कप जीत के बाद भारतीय महिला टीम स्थिरता और निरंतरता के दौर में है, लेकिन कप्तानी का सवाल अब टाला नहीं जा सकता। हरमनप्रीत ने कई सालों तक टीम का नेतृत्व किया है, पर उम्र और भविष्य की योजना को देखते हुए बीसीसीआई को दीर्घकालिक विकल्प की ज़रूरत है। ऐसे में लीडरशिप सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को साथ लेकर चलने की क्षमता भी अहम बन गई है।

5 जनवरी 2026 को दिए एक इंटरव्यू में मैरिज़ेन कैप ने जेमिमा रोड्रिग्स को भारत की अगली कप्तान के रूप में देखने की इच्छा जताई। कैप के अनुसार, जेमिमा में वर्षों से लीडरशिप के गुण दिखाई देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कप्तानी केवल फील्ड सेटिंग और फैसलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि टीम के भीतर विश्वास और एकता बनाना भी उतना ही जरूरी है–और जेमिमा इसमें स्वाभाविक रूप से आगे हैं।

कैप ने ज़ोर देकर कहा कि जेमिमा की सबसे बड़ी ताकत उनकी पर्सनैलिटी है। वह खिलाड़ियों को जोड़ती हैं, माहौल को सकारात्मक रखती हैं और हर खिलाड़ी की परवाह करती हैं। हाल ही में विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ खेली गई उनकी नाबाद 127 रनों की पारी ने यह भी साबित किया कि वह बड़े मंच और दबाव को संभाल सकती हैं। 25 साल की उम्र में इस तरह की परिपक्वता उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार बनाती है।

विजय हजारे ट्रॉफी 2026

वापसी की चर्चा के बीच विराट कोहली दिल्ली के लिए नहीं खेलेंगे अगला मैच

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली रेलवे के खिलाफ होने वाला विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का मैच नहीं खेलेंगे। दोनों राज्य एसोसिएशन बीसीसीआई के प्रमुख 50 ओवर के टूर्नामेंट के पांचवें राउंड में 6 जनवरी को आमने-सामने होने वाले थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विराट केएससीए क्रिकेट ग्राउंड पर रेलवे के खिलाफ दिल्ली के विजय हजारे ट्रॉफी मैच के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। रिपोर्ट में विराट की गैरमौजूदगी का कारण नहीं बताया गया है।

खास बात यह है कि इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने दिल्ली के लिए पहले दो मैच खेले और एक शतक और एक अर्धशतक लगाया। हालांकि वह अपने परिवार के पास लौट गए और पिछले दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच नहीं खेले। 37 साल के यह खिलाड़ी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल होने से पहले एक और वीएचटी मैच खेलने वाले थे। हालांकि अब यह भारतीय स्टार 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में सीधे न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक्शन में दिखेंगे।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 से पहले बोर्ड ने भारत के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को निर्देश दिया था कि अगर उन्हें वनडे के लिए टीम में बने रहना है तो उन्हें कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने होंगे। इसलिए रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और सभी बड़े खिलाड़ियों ने इस दिसंबर विंडो में अपने राज्य एसोसिएशन की जर्सी पहनी।

दिल्ली के लिए विराट कोहली के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच खेला और शानदार 131 (101) रन बनाए जिसमें 14 चौके और तीन छक्के शामिल थे। इसके बाद उन्होंने गुजरात का सामना किया और 77 (61) रन बनाए। अगर विराट अब आने वाला विजय हजारे ट्रॉफी मैच नहीं भी खेलते हैं, तो बीसीसीआई की तरफ से कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही उनकी बात मान ली है।

बीते वित्त वर्ष 49 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एफआईयू के पास पंजीकृत : रिपोर्ट

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 49 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के पास पंजीकृत हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से ज्यादातर भारत में स्थित हैं। यह पंजीकरण इस क्षेत्र से धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए देश की कानूनी व्यवस्था के तहत किया गया है। इन एक्सचेंजों द्वारा संघीय एजेंसी को दी गई संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) के विश्लेषण में पाया गया कि क्रिप्टो फंड का दुरुपयोग हवाला, जुआ, घोटाले, धोखाधड़ी और अवैध वयस्क सामग्री वाली वेबसाइट चलाने जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।

कानूनी भाषा में क्रिप्टो करेंसी को आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (वीडीए) कहा जाता है और इनमें व्यापार करने वाले एक्सचेंजों को वीडीए सेवा प्रदाता (वीडीए एसपी) कहा जाता है। इन एक्सचेंजों को 2023 में भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत लाया गया था। पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग संस्था होने के नाते, इन एक्सचेंजों को एफआईयू को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट सौंपनी होती है। एफआईयू एक संघीय एजेंसी है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली के किसी भी दुरुपयोग को रोकने और उसका पता लगाने के लिए काम करती है।

वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है और हाल के वर्षों में इसने वित्तीय क्षेत्र को बदलने की अपनी क्षमता के कारण ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट के अनुसार वीडीए और इनके सेवा प्रदाताओं के साथ धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण के कुछ संभावित जोखिम हैं। ऐसा इनकी वैश्विक पहुंच, तीव्र निपटान की क्षमता, सीधे लेनदेन की सुविधा और लेनदेन के प्रवाह तथा पक्षों की पहचान छिपाने की संभावना के कारण है। मार्च 2025 तक 49 वीडीए सेवा प्रदाता एफआईयू के पास रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में पंजीकृत थे, जिनमें से 45 एक्सचेंज स्वदेशी (भारत में स्थित) थे, जबकि बाकी चार विदेश में स्थित थे।

एशेज सिडनी टेस्ट : अश्विन का बड़ा रिकॉर्ड टूटा मिचेल स्टार्क ने 14वीं बार स्टोक्स को आउट किया

सिडनी **(एजेंसी)**। एशेज 2025-26 के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पर अपना दबदबा कायम रखते हुए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले की पहली पारी में स्टोक्स खाता भी नहीं खोल सके और स्टार्क की घातक गेंदबाजी का शिकार बन गए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, हालांकि जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच शतकीय साझेदारी जरूर बनी। ब्रूक के आउट होने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर आए, लेकिन वह 11 गेंदों तक टिकने के बावजूद खाता नहीं खोल पाए। पारी के 51वें ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पिच पर गिरने के बाद तेजी से उछली। स्टोक्स उछाल को संभाल नहीं सके और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। अंपायर ने शुरुआत में आउट नहीं दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने डीआरएस लिया। रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले को छूकर गई थी और स्टोक्स को पवेलियन लौटना पड़ा। इस विकेट के साथ ही मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया। टेस्ट क्रिकेट में यह 14वां मौका था जब स्टार्क ने बेन स्टोक्स को आउट किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन के नाम था, जिन्होंने स्टोक्स को 13 बार आउट किया था।

भारत-इजराइल व्यापार को रुपए में करने को बढ़ावा देगा एसबीआई

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों में गहराई लाने और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर जारी चर्चाओं के बीच इजराइल में उपस्थित एकमात्र भारतीय ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) रुपए में द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा है। एसबीआई इजराइल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वी. मणिवन्नन ने कहा, ''भारत के सहयोगी देशों से होने वाले महत्वपूर्ण व्यापार एवं वैश्विक व्यापार समुदाय में भारतीय रुपए में व्यापार करने की बढ़ती रुचि को देखते हुए, हमारे बैंकिंग नियामक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के निर्यात एवं आयात का निपटान भारतीय रुपए में करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत इजराइल को भागीदार देशों में से एक के रूप में चुना गया है।''

एसबीआई के अधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से निर्यात/आयात करने वाली इजराइली संस्थाएं भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त करेंगी और देंगी जिसे इजराइली विक्रेता/खरीदार से माल या सेवाओं की आपूर्ति/खरीद के 'इनवॉइस' के बदले विशेष रुपी वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) में जमा किया जाएगा।'' उन्होंने कहा, ''एसबीआई तेल अवीव के पास इन लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां मौजूद हैं।'' एसबीआई की शाखा ने हाल ही में इजराइल-भारत वाणिज्य चैंबर के सहयोग से रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई बैठकें एवं वेबिनार आयोजित किए। इन चर्चाओं में इजराइल की अधिकतर प्रमुख रक्षा संस्थाओं के अधिकारी शामिल हुए थे। हाल ही में 40, 000 से अधिक भारतीय कामगारों के इजराइल कार्यबल में शामिल होने के साथ एसबीआई, तेल अवीव शाखा में भारत में उनके अनिवासी प्रवासी खाते खोलने की सुविधा प्रदान करके भारत में प्रेषण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने की भी कोशिश कर रहा है। एसबीआई ने 2007 में इजराइल में अपनी शाखा खोली और तब से एक पूर्ण विकसित परिचालन बनाए रखने में सफल रहा है। यह वैश्विक महामारी तथा क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण दो वर्ष से अधिक समय तक चली उथल-पुथल के बावजूद इसकी दृढ़ता को दर्शाता है।

सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाना सामाजिक आर्थिक नजरिये से जरूरी : स्मृति ईरानी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाना सामाजिक के साथ आर्थिक नजरिये से भी जरूरी है। ईरानी ने यहां आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026 को संबोधित करते हुए कहा, महिलाओं को सफलता के शिखर पर भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय का दायित्व संभाल चुकीं ईरानी ने स्पार्क पहल का उल्लेख भी किया जिसका उद्देश्य 300 शहरों में एक लाख महिला उद्यमियों को ऋण, औपचारिकता और संस्थागत सहयोग तक पहुंच उपलब्ध कराना है।

सम्मेलन के दूसरे दिन एक अभियान की शुरुआत भी हुई, जिसका लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आर्थिक वृद्धि और रोजगार के प्रमुख चालक के रूप में मजबूत करना है। टाई के मुताबिक, यह पहल अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियां और 100 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए सरकारों, उद्योग संगठनों, पूंजी प्रदाताओं और विश्वभर के टाई चैप्टर को जोड़ा जाएगा।

मुख्य फोकस क्षेत्रों में नियामकीय सरलीकरण, पूंजी तक पहुंच, कौशल विकास, तकनीक अपनाना और क्लस्टर-आधारित क्षेत्रीय विकास शामिल हैं। एमएसएमई पर केंद्रित एक अन्य सत्र में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने स्थिर नियमों, आसान जीएसटी अनुपालन, बेहतर ऋण उपलब्धता और प्रौद्योगिकी-आधारित क्लस्टर विकास की भूमिका पर चर्चा की। सत्र के बाद आंध्र प्रदेश सरकार, टाई हैदराबाद और टाई विशाखापत्तनम के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। इससे पहले भविष्य के शहरों के निर्माण पर केंद्रित सत्र में वैश्विक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी पर चर्चा हुई।

भारत का यूरिया आयात अप्रैल-नवंबर में दोगुने से अधिक होकर 71.7 लाख टन हो गया : एफएआई

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। घरेलू उत्पादन में गिरावट से चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीने में भारत का यूरिया आयात दोगुने से अधिक होकर 71.7 लाख टन हो गया है जो किसानों की मांग को पूरा करने के लिए विदेशी आपूर्ति पर देश की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2024-25 के दौरान यूरिया का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 32.6 लाख टन की तुलना में 120.3 प्रतिशत बढ़कर 71.7 लाख टन हो गया। आंकड़ों के अनुसार, घरेलू यूरिया उत्पादन अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 के बीच 3.7 प्रतिशत घटकर 1.97 करोड़ टन रहा। कुल यूरिया बिक्री 2.3 प्रतिशत बढ़कर 2.54 करोड़ टन तक पहुंच गई। एफएआई के चेयरमैन एस. शंकर सुब्रमण्यम ने एक बयान में कहा, ''हालांकि हमने समन्वित योजना के माध्यम से बिक्री में वृद्धि हासिल की है लेकिन आयात पर महत्वपूर्ण निर्भरता (विशेष रूप से यूरिया और डीएपी के लिए) रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के महत्व को दर्शाती है।'' यूरिया का आयात नवंबर माह में 68.4 प्रतिशत बढ़कर 13.1 करोड़ टन हो गया, जबकि नवंबर 2024 में यह 7.8 लाख टन था। यूरिया की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में नवंबर माह में 4.8 प्रतिशत बढ़कर 37.5 लाख टन हो गई। अन्य महत्वपूर्ण मृदा पोषक तत्व, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आयात पर निर्भरता भी बढ़ रही है। डीएपी का आयात अब कुल आपूर्ति का 67 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष 56 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-नवंबर के दौरान इसकी बिक्री 71.2 लाख टन पर स्थिर रही। घरेलू डीएपी उत्पादन में 5.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 26.8 लाख टन रह गया। एफएआई के महानिदेशक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी ने कहा कि इन आंकड़ों में दो प्रमुख बातें सामने आई हैं।

उन्होंने कहा, ''पहला, नाइट्रोजन और फॉस्फेट पोषक तत्वों के लिए आयात-आधारित आपूर्ति प्रबंधन की ओर संरचनात्मक बदलाव है। दूसरा, एसएसपी जैसे स्वदेशी फॉस्फेट उर्वरकों का मजबूत प्रदर्शन है जिनकी बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।'' चौधरी ने कहा, ''यह एक संतुलित दृष्टिकोण का संकेत है। हम नियोजित आयात के माध्यम से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को सुरक्षित कर रहे हैं। साथ ही घरेलू स्तर पर फॉस्फेट उत्पादन को भी मजबूत कर रहे हैं। भविष्य में एफएआई, सतत कृषि को समर्थन देने के लिए डेटा-आधारित योजना और पोषक तत्वों के उपयोग में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।'' केंद्र सरकार द्वारा यूरिया पर सब्सिडी दी जाती है। एक नवंबर 2012 से इसकी कीमत 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बोरा (नीम कोटिंग शुल्क व करों को छोड़कर) पर यथावत है।

रोजगार संकट से निपटने के लिए उद्योग जगत की बड़ी पहल, 10 करोड़ जॉब्स का प्लान

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। देश में रोजगार की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों ने सोमवार को 'हंड्रेड मिलियन जॉब्स' नाम से एक बड़ी राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की। इस मिशन का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत में 10 करोड़ नए रोजगार अवसर पैदा करना है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब देश तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद पर्याप्त रोजगार सृजन की समस्या से जूझ रहा है।

इस पहल की घोषणा सॉफ्टवेयर उद्योग संगठन नैसकॉम के सह-संस्थापक हरीश मेहता, वैश्विक उद्यमी नेटवर्क द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के संस्थापक ए. जे. पटेल और सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी के संस्थापक यतीश राजावत ने संयुक्त रूप से की।

संस्थापकों के मुताबिक, भारत में कार्यशील आयु की आबादी हर साल लगभग 1.2 करोड़ की दर से बढ़ रही है, जबकि विनिर्माण जैसे पारंपरिक रोजगार क्षेत्र अपेक्षित गति से विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में देश को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा फायदा उठाने के लिए हर साल 80 से 90 लाख नई नौकरियां सृजित करने की जरूरत है।

हालांकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन रोजगार की रफ्तार उत्पादन और आर्थिक विस्तार के मुकाबले पीछे रही है। स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से कई क्षेत्रों में शुरुआती स्तर की नौकरियां कम हो रही हैं, जिससे यह आशंका गहराने लगी है कि आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के बीच दूरी बढ़ सकती है।

हंड्रेड मिलियन जॉब्स' मिशन के तहत उद्यमिता, कौशल विकास और श्रम-प्रधान उद्योगों को भारत की रोजगार नीति के केंद्र में रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य रोजगार सृजन को आर्थिक प्रगति का प्रमुख पैमाना बनाना है।

विनीत कुमार सिंह और सैयामी खेर ने अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग शुरू की

अभिनेता विनीत कुमार सिंह ने नई एनर्जी और एक्साइटिंग प्लान्स के साथ नए साल की शुरुआत की है। 2025 में लगातार हिट फिल्मों, जिसमें उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक 'छावा' भी शामिल है, के बाद, 2026 विनीत के लिए ज़ोरदार तरीके से शुरू हो रहा है। एक्टर ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइनर से डायरेक्टर बने विक्रम फडनिस के साथ हाथ मिलाया है। विनीत ने कहानी को 'खूबसूरत' और अपने दिल के करीब बताया है, हालांकि अभी डिटेल्स को सीक्रेट रखा गया है।

विनीत कुमार सिंह और सैयामी खेर ने अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। सिंह ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की। इस पोस्ट में पूजा समारोह की तस्वीरों और वीडियो के साथ फिल्म के 'क्लैपर बोर्ड' की एक तस्वीर भी थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, इस खूबसूरत कहानी को आप सभी के सामने लाने के लिए उत्साहित हूं! फिलहाल, इस प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और कुछ कमाल करते हैं।

विक्रम फड़नीस द्वारा निर्देशित इस फिल्म का अभी नाम नहीं रखा गया है। इसमें ताहिर राज भसीन भी काम कर रहे हैं। सैयामी खेर जल्द ही अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ फिल्म हैवान में दिखाई देंगी। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रिया पिलगांवकर भी हैं। विनीत कुमार सिंह हाल ही में फिल्म तेरे इश्क में में नजर आए थे। नवंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में कृति सैनन और धनुष मुख्य भूमिकाओं में थे और इसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया था। फिल्म में सिंह ने वी शेखावत का किरदार निभाया था।

युवा के राउंडटेबल शो 'बी ए मैन, यार' में, विनीत कुमार सिंह ने अपने शुरुआती करियर के मुश्किल दौर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि, अपने स्ट्रगल के दिनों में, इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए उन्हें कई छोटी और अजीब नौकरियां करनी पड़ीं। विनीत ने बताया कि उन्होंने सुनील शेट्टी के बॉडी डबल के तौर पर भी काम किया और बैकग्राउंड रोल किए जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं खींचते थे। उनके लिए, वे अनुभव उनकी यात्रा का हिस्सा थे और उन्होंने उन्हें अपने सपने से जुड़े रहने में मदद की। उन्होंने समझाया कि ऐसे समय में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अंदर से मज़बूत रहें और हार न मानें।

जागरण में बेकाबू हुईं सुधा चंद्रन, भजन गाया फिर जोर-जोर से हंसने लगीं, क्या माता चढ़ी?

नागिन में हाल ही में नज़र आईं एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का एक नया क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस क्लिप में, अनुभवी एक्ट्रेस भजन में शामिल होते समय एक अजीब सी हालत में दिखीं। जब भजन में मौजूद कई दूसरे लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उन्हें काट भी लिया। दूसरे भक्तों ने बताया कि भक्ति के उस पल में ऐसा लग रहा था कि उन पर किसी आत्मा का साया है।

सुधा हॉल में इधर-उधर कूदती हुई दिखीं, वह अपने इमोशन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने लाल और सफेद साड़ी पहनी थी, साथ ही माथे पर एक हेडबैंड बांधा हुआ था जिस पर 'जय माता दी' लिखा था। जैसे-जैसे भजन चलता रहा, एक्ट्रेस इमोशनली बहुत ज़्यादा भावुक हो गईं और अपने हाव-भाव पर कंट्रोल खो बैठीं। एक समय पर, दूसरे लोग उन्हें पकड़ने और उन्हें कंट्रोल में लाने में मदद करने के लिए आगे आए। सुधा एक ऐसे आदमी के हाथ काटती हुई दिखीं जिसने उनकी मदद करने की कोशिश की थी। एक समय पर, तीन लोग उन्हें पकड़े और सहारा देते हुए दिखते हैं ताकि वह गिरें नहीं या खुद को चोट न पहुंचा लें। माना जा रहा है कि यह फुटेज एक धार्मिक कार्यक्रम का है जहां सुधा चंद्रन माता के भजन में हिस्सा ले रही थीं। जैसे-जैसे भक्ति गीत तेज़ होते हैं, उनके हाव-भाव और ज़्यादा साफ होने लगते हैं, जिससे उनके आस-पास के लोग उन्हें संभालने के लिए आगे आते हैं। इस वीडियो पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, कई लोगों ने इस पल को पूजा के दौरान एक गहरी आध्यात्मिक समाधि बताया है।

सुधा को नागिन फ्रैंचाइज़ी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी अटेंशन मिला, जहाँ उन्होंने पहले दो सीज़न में चालाक माँ यामिनी रहेजा का किरदार निभाया था। उन्होंने ये हैं मोहब्बतें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और माता की चौकी, कलयुग में भक्ति की शक्ति जैसे टीवी शो में भी काम किया है। पिछले कुछ सालों में, उन्होंने फिल्मों में दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को इम्प्रेस किया है और काहीं किसी रोज़, नागिन 6, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे पॉपुलर शो के ज़रिए टेलीविज़न पर घर-घर में मशहूर हो गईं। दशकों लंबे करियर के साथ, सुधा चंद्रन अपनी प्रतिभा, ताकत और दर्शकों के साथ गहरे जुड़ाव के लिए - स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर दोनों जगह - तारीफ बटोर रही हैं।

दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कार्यकर्ताओं-- उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सोमवार को स्वागत करते हुए कहा कि शहर को दंगों की आग में धकेलने के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों-- उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया लेकिन ''भागीदारी के स्तर'' का हवाला देते हुए पांच अन्य को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि खालिद और इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

गुप्ता ने यहां 'पीटीआई-

वीडियो' से कहा, ''हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपियों-- शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।''

उन्होंने कहा कि दंगों में शामिल लोगों का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए कड़ा संदेश जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ''अपराध में भागीदार'' थीं।

दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दंगे एक ''सुनियोजित साजिश'' का नतीजा थे।

उन्होंने कहा, ''दिल्ली की जनता के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची गई थी। आज के फैसले ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया है।'' उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्पष्ट संदेश मिलता है कि ऐसी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अदालत का यह आदेश देश के खिलाफ काम करने वालों के लिए एक मिसाल बनेगा। सूद ने कहा, 'सरकार का विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन देश का विरोध करना अलग बात है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के खिलाफ काम करने के आरोपियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं।'

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दंगाइयों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कड़ा संदेश देने के लिए उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया। फरवरी 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

तेलंगाना राजनीति : केसीआर से के. कविता की बगावत बीआरएस छोड़ बोलीं- सच बोलने की सजा मिली

हैदराबाद **(एजेंसी)**। तेलंगाना की एमएलसी के. कविता ने सोमवार को तेलंगाना विधान परिषद में भावभीनी विदाई भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सदन से अपने इस्तीफे और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से अलग होने के अपने निर्णय की औपचारिक घोषणा की। अपने लंबे सार्वजनिक और राजनीतिक सफर और पार्टी से निलंबन से जुड़ी परिस्थितियों का जिक्र करते हुए वे भाषण के दौरान भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि वे केसीआर और प्रोफेसर जयशंकर से प्रेरित होकर 2006 में तेलंगाना आंदोलन में शामिल हुईं और जागृति के माध्यम से स्वतंत्र रूप से महिलाओं और युवाओं को संगठित करने, तेलंगाना की संस्कृति की रक्षा करने, इसके इतिहास का दस्तावेजीकरण करने और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों और स्थानीय रोजगार के लिए संघर्ष करने का काम किया।

कविता ने स्पष्ट किया कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच-विचार के बाद बीआरएस द्वारा दिए गए निजामाबाद संसदीय टिकट को स्वीकार कर लिया। तेलंगाना के गठन के बाद, उन्होंने विभाजन के बाद के प्रमुख मुद्दों और विकास परियोजनाओं पर काम करना जारी रखा, जिसमें लंबे समय से लंबित पेद्दापल्ली-निजामाबाद रेलवे लाइन को पूरा करना भी शामिल है। अपने योगदान के बावजूद, उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था, फिर भी वह साहस और दृढ़ विश्वास के साथ श्रमिकों, महिलाओं और वंचितों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध रहीं।

उन्होंने कहा कि केसीआर के आउटसोर्सिंग के विरोध के बावजूद, राज्य गठन के बाद ठेका प्रणाली का विस्तार किया गया। जब उन्होंने इन निर्णयों पर सवाल उठाए, तो पार्टी ने उनके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया और एक साजिश के तहत उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। उन्होंने धरना चौक को हटाए जाने, किसानों की गिरफ्तारी, प्रमुख सार्वजनिक परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण पर चिंता व्यक्त की। सच बोलने के कारण उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया, जबकि तेलंगाना कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, उन्हें पेंशन से वंचित रखा गया और यहां तक कि 1969 के आंदोलन के दिग्गजों को भी मान्यता नहीं दी गई। उन्होंने आगे कहा कि 'जल, निधि और नियुक्तियां' का मूल वादा लगातार कमजोर होता गया और भ्रष्टाचार को बार-बार उजागर करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी बताया कि बोधन चीनी कारखाने के लिए दस वर्षों से अधिक समय तक उनके बार-बार किए गए अनुरोधों को नजरअंदाज किया गया।

केसीआर की बेटी होने के नाते, उन्होंने कहा कि उनमें उनसे सीधे सवाल करने का साहस था। हालांकि एक-दो अनुरोधों का कार्यान्वयन न होना वह स्वीकार कर सकती थीं, लेकिन गंभीर अन्याय की बार-बार की उपेक्षा अस्वीकार्य थी। उन्होंने पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस करने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह तेलंगाना की उपेक्षा करते हुए राष्ट्रीय विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।

शिफा उर रहमान की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत का किया स्वागत

उमर और शरजील की जल्द रिहाई की उम्मीद जताई

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित तौर पर रची गई एक बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। शिफा उर रहमान की पत्नी ने फैसले का स्वागत किया और वकीलों की टीम को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।

एएनआई से बात करते हुए शिफा उर रहमान की पत्नी ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और वकीलों को धन्यवाद देते हैं... उम्मीद है उमर खालिद और शरजील इमाम को भी जल्द से जल्द जमानत मिल जाएगी। आज सुबह, गुलफिशा फातिमा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सरिम जावेद ने पांचों आरोपियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश को उनके और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया। वकील ने जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पांचों आरोपियों का दोष, यदि कोई है, तो सीमित प्रकृति का प्रतीत होता है।

जावेद ने यह भी बताया कि अन्य दो आरोपी, उमर खालिद और शरजील इमाम, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया

था, एक साल बाद दोबारा आवेदन कर सकते हैं। एएनआई से बात करते हुए जावेद ने कहा, 'जिन पांच लोगों को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उनका कोई दोष है भी तो वह बहुत कम है। जिन दो लोगों को जमानत नहीं मिली है, उनके दोष पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मामले की संरचना को देखते हुए और संविधान तथा यूएपीए दोनों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी संरक्षित गुप्त गवाहों को एक साल का समय दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उमर खालिद और शरजील इमाम एक साल बाद जमानत के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं... यह उनके और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है।

दिल्ली के सार्वजनिक कोष पर केंद्र का शिकंजा, एमएचए ने जारी किया उपराज्यपाल के लिए नया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्र सरकार ने पहली बार 9 जनवरी को वह तिथि अधिसूचित की है, जिस दिन दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी सार्वजनिक धन को एक निर्दिष्ट सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में ऐसे धन के लेखांकन ढांचे को औपचारिक रूप दिया गया है।

यह निर्णय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 की धारा 46ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। 2 जनवरी को जारी अधिसूचना में 'राजधानी का सार्वजनिक खाता' नामक एक विशिष्ट सार्वजनिक खाते के निर्माण और संचालन का प्रावधान है। अधिसूचना के अनुसार, 9 जनवरी से उपराज्यपाल द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी 'अन्य सार्वजनिक धन' अनिवार्य रूप से इस नव-निर्दिष्ट खाते में जमा किए जाएंगे। 'अन्य सार्वजनिक धन' शब्द में व्यापक रूप से वे निधियां शामिल हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन सार्वजनिक प्राधिकरण के प्रयोग में प्राप्त होती हैं, जिनमें उपराज्यपाल के अधिकार के तहत संभाले जाने वाले कुछ जमा, प्रेषण और प्राप्तियां शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 (1 ऑफ 1992) की धारा 46ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 9 जनवरी, 2026 को वह तिथि नियुक्त करती है जिस दिन से उपराज्यपाल द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन 'राजधानी का सार्वजनिक खाता' नामक सार्वजनिक खाते में जमा किए जाएंगे।

महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीते तो एमएनएस ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग से आग्रह

मुम्बई **(एजेंसी)**। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने सोमवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से संपर्क कर ठाणे नगर निगम और राज्य के अन्य नगर निकायों में निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के चुनाव परिणामों पर रोक लगाने का आग्रह किया। एमएनएस नेता अविनाश जाधव के नेतृत्व में एक पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने एसईसी से मुलाकात कर गहन जांच की मांग की। एमएनएस के ठाणे और पालघर जिला अध्यक्ष जाधव ने कहा कि जांच एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हों। पार्टी ने ठाणे नगर निगम चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। विपक्षी उम्मीदवारों, जिनमें एमएनएस के उम्मीदवार भी शामिल हैं, या तो पैसों का लालच दिया गया या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी से उनके नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। इसके परिणामस्वरूप सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे समूह) के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर आघात है।

महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। शुक्रवार (2 जनवरी) नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, और इसके समाप्त होते ही महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। महायुति

में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं। निर्विरोध विजयी हुए महायुति के 68 उम्मीदवारों में से 44 भाजपा से, 22 शिवसेना से और दो एनसीपी से थे। हालांकि, अनियमितताओं के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने शनिवार (3 जनवरी) को जांच के आदेश दिए।

इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-यूबीटी ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। गौरतलब है कि शिवसेना-यूबीटी और एमएनएस ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए गठबंधन किया है। संजय राउत ने कहा कि मेरे एक मित्र, जो इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं, ने कहा कि (दोपहर 3 बजे के बाद फॉर्म स्वीकार करना) उचित नहीं होगा।

निकोलस मादुरो का भारत कनेक्शन! सत्य साईं बाबा के भक्त कैसे बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति?

काराकास **(एजेंसी)**। वेनेजुएला के राष्ट्रपति माधुरो को आज दुनिया का विवाद और सख्त शासक के रूप में जानती है। लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचने से पहले उनका जीवन बेहद साधारण और संघर्षों से भरा रहा है। उनकी कहानी केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें मेहनतकश जीवन ट्रेड यूनियन आंदोलन और भारत के एक आध्यात्मिक गुरु से जुड़ा अनोखा विश्वास भी शामिल है। माधुरो का जन्म 23 नवंबर 1962 को वेनेजुएला के राजधानी काराकस में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता मजदूर संगठनों से ही जुड़े थे। जिससे सामाजिक असमानता और श्रमिक अधिकारियों के मुद्दों, माधुरों ने बचपन से ही गरीबी देखी है। आर्थिक परिस्थितियों के चलते वह उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पाए और युवा व्यवस्था में ही रोजगार की तलाश में निकल पड़े। इसी दौरान उन्होंने काराकास में बस ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू किया। काराकास

की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर बस चलाते हुए मादुर को आम लोगों की परेशानियों को बेहद करीबी से समझने का मौका मिला।

2023 में शावेज के निधन के बाद माधुरों को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना गया। उसी साल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बेहद करीबी मुकाबलों में जीत हासिल की और वेनेजुला के राष्ट्रपति बन गए। हालांकि उनके शासनकाल की पहचान आर्थिक संकट, महंगाई, खाद संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ गई। राजनीति के अलावा निकोल्स मादुर की एक और पहचान है जिसने खासकर भारत में लोगों का ध्यान खींचा है।

गिरफ्तार किए गए वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर एक रोचक पहलू सामने आया है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मादुरो दिवंगत भारतीय आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा के भक्त रहे हैं। वे कैथोलिक परिवार में पले-बढ़े थे, लेकिन उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के प्रभाव में आकर साईं बाबा के अनुयायी बने। साल 2005 में मादुरो और फ्लोरेस भारत आए थे और पुट्टपर्थी में साईं बाबा से मुलाकात की थी। उस समय फ्लोरेस पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ की वकील थीं और मादुरो संसद के स्पीकर थे। बाद में मादुरो विदेश मंत्री बने। साईं बाबा के निधन पर वेनेजुएला की संसद ने शोक प्रस्ताव पास किया और एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया।

दुनिया में थू-थू के बाद अमेरिका की सफाई वेनेजुएला पर कोई आक्रमण नहीं, मादुरो की गिरफ्तारी

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर उठे अंतर्राष्ट्रीय विवाद के बीच ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कोई युद्ध या सैन्य आक्रमण नहीं, बल्कि कानून-प्रवर्तन की सीमित कार्रवाई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला से नहीं, बल्कि ड्रग तस्करी संगठनों से लड़ रहा है। एनबीसी के कार्यक्रम प्रेस से मिलो में रुबियो ने कहा, 'कोई युद्ध नहीं है। अमेरिका वेनेजुएला से युद्ध में नहीं, बल्कि ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई में है।'

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून के तहत एक अभियुक्त नार्को-तस्कर की गिरफ्तारी के लिए किया गया और इसे किसी भी तरह से आक्रमण या सैन्य कब्जा नहीं कहा जा सकता। रुबियो ने एबीसी के इस सप्ताह कार्यक्रम में बताया कि अमेरिकी बल केवल थोड़े समय के लिए जमीन पर थे, उन्होंने गिरफ्तारी को अंजाम दिया और फिर वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए अदालत के वारंट और प्रतिबंध कानूनों का इस्तेमाल किया गया, न कि कांग्रेस से किसी युद्ध अनुमति का। सीबीएस के राष्ट्र का सामना करें पर रुबियो ने कहा कि अब अमेरिका का फोकस दीर्घकालिक दबाव पर है। इसके तहत प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा और समुद्री रास्तों से होने वाले तेल व्यापार पर 'तेल क्वारंटीन' लगाया जा रहा है। अदालतों के आदेश के जरिए प्रतिबंधित तेल शिपमेंट को जब्त किया जा रहा है।

रुबियो ने यह भी साफ किया कि अमेरिका वेनेजुएला का प्रशासन नहीं चला रहा। 'हम देश नहीं चला रहे, हम अपनी नीति चला रहे हैं।' उन्होंने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ड्रग तस्करी रोकना, गैंग्स को खत्म करना और विदेशी चरमपंथी

संगठनों की मौजूदगी समाप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा बताया। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह हमारा क्षेत्र है। हम इसे अपने विरोधियों का ऑपरेशन बेस नहीं बनने देंगे।' वॉल्ट्ज ने मादुरो के चीन, रूस, ईरान और हिज़्बुल्ला से कथित संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम जरूरी था।अमेरिका ने फिलहाल वेनेजुएला में स्थायी अमेरिकी सेना की मौजूदगी से इनकार किया है। साथ ही राजनीतिक बदलाव और चुनावों को लेकर रुबियो ने कहा कि यह प्रक्रिया समय लेती है और अमेरिका वादों नहीं, कार्रवाइयों के आधार पर आगे के कदम तय करेगा।

ट्रंप ने मादुरो को 'नरक समान' सबसे खतरनाक जेल में किया बंद, खुद जज भी कैदी वहां भेजने से हैं डरते

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (एमडीसी) में रखा गया है। यह वही जेल है, जो वर्षों से गंभीर अव्यवस्थाओं, हिंसा और अमानवीय हालात को लेकर विवादों में रही है। हालात इतने खराब बताए गए हैं कि कुछ अमेरिकी न्यायाधीशों ने यहां आरोपियों को भेजने से तक इनकार किया है। 1990 के शुरुआती वर्षों में शुरू हुई यह संघीय जेल फिलहाल करीब 1, 300 कैदियों का घर है। मैनहैटन और ब्रुकलिन की संघीय अदालतों में पेश होने वाले आरोपियों को आमतौर पर सबसे पहले यहीं रखा जाता है। यहां कथित गिरोह सदस्यों, मादक पदार्थ तस्करों के साथ-साथ सफेदपोश अपराधों के आरोपी भी बंद रहते हैं।

तीन जनवरी की रात मादुरो के पकड़े जाने की खबर सामने आते ही बड़ी संख्या में वेनेजुएला के प्रवासी, हाथों में राष्ट्रीय झंडे लिए, जेल के बाहर जमा हो गए और जश्न मनाया। जब मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गाड़ियां जेल पहुंचीं, तो भीड़ ने नारे लगाए। मादुरो इस जेल में बंद होने वाले पहले राष्ट्रपति नहीं हैं। इससे पहले होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज़ भी इसी जेल में रखे गए थे। उन पर अमेरिका में सैकड़ों टन कोकीन की तस्करी का मुकदमा चला था। दोषी ठहराए जाने और 45 साल की सजा के बाद उन्हें दिसंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माफी देकर रिहा कर दिया था।

वर्तमान में एमडीसी ब्रुकलिन में मेक्सिको के सिनालोआ ड्रग कार्टेल के सह-संस्थापक इस्माइल 'एल मायो' ज़ाम्बाडा गार्सिया और यूनाइटेडहेल्थकेयर के सीईओ की हत्या के आरोपी लुइगी मैनजियोनी जैसे चर्चित कैदी भी बंद हैं। अतीत में यहां क्रिप्टो उद्यमी सैम बैंकमैन-फ्राइड और जेफ्री एपस्टीन की सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल भी रह चुकी हैं। समुद्र तट के औद्योगिक इलाके में, एक शॉपिंग मॉल के पास स्थित यह जेल दूर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के करीब दिखाई देती है, लेकिन भीतर के हालात को कई बार 'नरक समान' और 'लगातार चल रही त्रासदी' बताया गया है। कैदियों और उनके वकीलों ने यहां लंबे समय से हिंसा और असुरक्षा की शिकायतें की हैं।

पाकिस्तान में आतंकी हिंसा तेजः फैक्टरी कर्मियों को ले जा रहे वाहन पर हमला, एक की मौत व 8 घायल

पेशावर **(एजेंसी)**। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार को एक वाहन को निशाना बनाकर किए गए 'इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस' (आईईडी) विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस के प्रवक्ता कुदरतुल्ला के अनुसार, यह विस्फोट अशांत लक्की मरवत जिले में बेगूखेल रोड पर नवारा खेल इलाके के पास हुआ। वाहन में एक सीमेंट फैक्टरी के कर्मचारी सवार थे, जिसे विस्फोट में निशाना बनाया गया। अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. किफायत बेट्टानी ने बताया कि घायलों में से दो की हालत गंभीर है।

एक अलग बयान में पुलिस ने कहा कि घटना के तुरंत बाद लक्की मरवत के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) नजीर खान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इलाके की घेराबंदी कर व्यापक तलाश अभियान शुरू किया गया। बयान में डीपीओ के हवाले से कहा गया कि यह 'कायराना कृत्य' क्षेत्र की शांति भंग करने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस हाई अलर्ट पर है और जान-माल की सुरक्षा के लिए 'सभी संभव कदम' उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में 2025 के दौरान भले ही उग्रवादियों की मौतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर रही, लेकिन उग्रवादी हिंसा में वृद्धि दर्ज की गई। आतंकवादी हमलों में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आतंकवाद से संबंधित मौतों में 21 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद स्थित 'पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज' के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में देशभर में कुल 699 आतंकवादी हमले दर्ज किए गए जिनमें कम से कम 1, 034 लोगों की जान गई और 1, 366 लोग घायल हुए।

पाकिस्तान की ऐसी फजीहत नहीं हुई होगी कभी, भरी सभा में चीन ने उतार दी इज्जत

इस्लामाबाद **(एजेंसी)**। सूटेड बूटेड होकर एक बार नहीं दो बार मुल्ला मुनीर ट्रंप के लंच में पहुंचे। पूरी दुनिया में घूम-घूम कर कहने लगे कि उन्होंने तो व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ खाना खाया। लेकिन मुनीर का यह इतराना ट्रंप के लिए पाकिस्तान का नोबेल पीस प्राइज के लिए नाम प्रस्तावित करना चीन को खल गई। जिनपिंग ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। अमेरिका से नजदीकी पर जिनपिंग ने पाकिस्तान को धो डाला है। चीन का पाकिस्तान पर भरोसा कम हो गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार चीन दौरे पर पहुंचे हैं। इशाक डार सातवें पाकिस्तान चीन रणनीतिक संवाद में शामिल हुए। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को बेहद अच्छा दोस्त कहते रहे हैं। लेकिन डार्क की इस यात्रा में माहौल कुछ अलग दिख रहा है। इसकी वजह है चीन का भरोसा पाकिस्तान पर कम हुआ है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़ी नजदीकी से राष्ट्रपति जिनपिंग नाराज हैं। ऐसे में चीनी सरकार पाकिस्तान से अमेरिका के साथ रिश्तों पर जानकारी मांग रही है। मतलब शाहबाज शरीफ एंड मुल्ला मुनीर दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ है अमेरिका जिसके बूते मुनीर फड़फड़ा रहा है। ट्रम्प पाकिस्तान को मदद का भरोसा दे रहे हैं। दूसरी ओर है चीन जिसके कर्ज के बिना पाकिस्तान का जीना मुश्किल है।

अब जिनपिंग पाकिस्तान से गुस्सा हो गए हैं। मतलब पाकिस्तान के लिए इधर कुआं है और उधर खाई। पाकिस्तान दोनों नावों पर सवारी नहीं कर सकता। चीन की अब तक की समझ थी कि पाकिस्तान उसके रहमोकरम पर पलता है। लेकिन ट्रंप के साथ दावत के बाद मुल्ला मुनीर की इच्छाएं परवान चढ़ने लगी तो चीन ने सीधा जमीन पर लापटका है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान की ओर से अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा रणनीतिक और आर्थिक संबंधों की जानकारी दी जाए। चीन ने पाकिस्तान से अमेरिका के साथ उसके बदलते रिश्तों की डिटेल मांगी है।

मंत्र भारत : R.N.I. UPHIN/2012/52437 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा श्री बालाजी प्रिंटर्स टिकरी, कमला नगर, प्रयागराज से मुद्रित एवं 80-ए मेहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 से प्रकाशित एवं सम्पादित।
● सम्पादक विनीता शर्मा ● मोबाइल : 9415975437, 7007837917, 9415223357 ● E-Mail : editormantrabharat@gmail.com ● वैधानिक सूचनाः- मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे का क्षेत्र प्रयागराज न्यायालय होगा।